श्री शंकर दयाल सिंह : धनबाद के भूतपूर्व संसद सदस्य श्री शंकर दयाल सिंह की मृत्यु हुई है। हम सब उनकी मृत्यु पर संवेदना प्रकट करते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him finish. Don't interrupt. It is a very serious matter.

श्री शंकर दयाल सिंह : उनकी जो मृत्यु हुई है हम सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: We do not know whether he is really alive or it is his ghost.

श्री शंकर दयाल सिंह : . . . कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन महोदया, मैं यह चाहता हूं कि आपके माध्यम से मेरे शुभचिन्तकों और देश के लोगों और माननीय सदस्यों को यह जानकारी मिल जाय कि मैं अभी हूं और मैं अभी रहूंगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरी इस चिंता को दूर करवा दें।

(Interruptions)

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): Madam, I just want to say that the whole House wishes him a long life and I say, long live Shri Shankar Dayal Singh.

THE DEUPTY CHAIRMAN: Mr. Gurupadaswamy, let me first announce that he is still alive, only then can you wish him a long life. Now from the Chair it is announced that he is alive...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : कल समाचार पत्रों में यह न छपे कि खेद के साथ लिखना पड़ता है कि यह समाचार गलत था।

SHRI SURESH KALMADI (Maharashtra): Please inform his family also.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That will be looked after later on. Now we take up the Calling attention to matter of urget public importance.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Acute power shortage in the country

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : (बिहार): मैं उपसभापति महोदया, देश में विद्युत की अत्यधिक कमी तथा इस स्थिति में सुधार करने के लिए उठाए गए कदमों की ओर विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): उपसभापति महोदया, देश में विद्युत की कमी के संबंध में माननीय सदस्यों की चिंता से मैं सहमत हूं इस समय विद्युत की कमी का मुख्य कारण, विद्युत के उत्पादन की तुलना में इसकी अधिक मांग होना है। इसके साथ-साथ देश के अनेक भागों में मानसून में विलम्ब होने तथा सामान्य से कम वर्षा होने के कारण कृषि क्षेत्र में विद्युत की मांग में काफी वृद्धि हुई है।

2 श्रीमन मैं सदन को इस बारे में अवश्वस्त करना चाहूंगा कि विद्युत की उपलब्धता में बढोतरी करने के लिए सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। योजना आयोग को प्रस्तुत आठवीं योजना संबंधी प्रस्ताव 38000 मेगावाट क्षमता जोड़े जाने की योजना है। स्वीकृत प्रस्तावों से लगभग 27189 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता चालू किए जाने की संभावना है। वर्ष 1990-91 के दौरान 2776.5 मेगावाट क्षमता जोड़ी गई है जिसमें से 732 मेगावाट केन्द्रीय क्षेत्र में और 2044.5 मेगावाट राज्य क्षेत्र में जोडी गई है। 1990-91 के दौरान विद्युत उत्पादन 264 यूनिट रहा जोकि 1989-90 की तुलना में 7.8 प्रतिशत अधिक है।

3. 31.3.1991 की स्थिति के अनुसार देश में कुल प्रतिष्ठापित क्षमता में ताप विद्युत

का हिस्सा लगभग 69.2 प्रतिशत है। इस प्रकार विद्युत की उपलब्धता, काफी हद तक ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन पर निर्भर करती है। 1990–91 के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार गुणक 53.8 प्रतिशत तक पहुंच गया था जबकि 1985–86 में यह 52.4 प्रतिशत था। संयंत्र भार गुणक में और किए जाने हेतु उपाय किए जा रहे है। पुराने विद्युत संयंत्रों के संयंत्र भार गुणक में सुधार करने के लिए नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप विद्यमान यूनिटों के विद्युत उत्पादन में और वृद्धि होगी।

चालू वर्ष में अप्रैल से जून के दौरान विद्युत उत्पादन 67.689 बिलियन यूनिट था जोकि गतवर्ष की इसी अवधि के के विद्युत उत्पादन से 6.4 प्रतिशत अधिक है। तथापि चालू वर्ष में अप्रैल से जन के दौरान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों ने 10 प्रतिशत से अधिक विद्युत की कमी का सामना किया। इनमें से अधिकांश राज्य अधिकता अथवा पूर्णतः जल विद्युत उत्पादन पर निर्भर करते है। बिजली की कमी वाले क्षेत्रों कों पड़ोसी प्रणालियों के द्वारा यथासंभव सहायता की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ–साथ प्राथमिकता प्रदान किए जाने संबंधी पद्धति के अनुक्रम में मांग प्रबंध उपाय भी क्रियान्वित किए जा रहे है। ऐसा करते हुए कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है और इसकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी की जा रही हैं।

5. केन्द्रीय क्षेत्र के केन्द्रों ने कार्य–निष्पादन का उच्च स्तर बनाए रखा और 1991–92 की प्रथम तिमाही के दौरान 58.6 प्रतिशत संयंत्र भार गुणक प्राप्त किया जोकि गतवर्ष की इसी अवधि की तुलना में 57.8 प्रतिशत था। यह विद्युत की कमी को घटाने में सहायक रहा। केन्द्रीय विद्युत उत्पादन की बढ़ती हुई भागीदारी के कारण विद्युत स्थिरता में और सुधार होने की आशा है।

6. देश में पारेषण और वितरण हानियों की मात्रा अत्यधिक रही है जोकि 21 प्रतिशत से 22 प्रतिशत के बीच थी। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने, राज्य बोर्डों द्वारा अपनी प्रणालियों में पारेषण एवं हानियों को कम किए जाने के लिए व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को समय–समय पर, अद्यतन किया जाता है। हानियों को कम करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को प्रणालीगत हानियों के लिए उत्तरदायी घटकों का पता लगाने के लिए व्यापक अध्ययन कार्य करने पड़ते है और प्रणाली में सुधार करने के लिए स्कीमें तैयार करनी पड़ती हैं तथा समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार इनको क्रियान्वित करना पड़ता है। पारेषण और वितरण हानियों को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1987 में एक प्रोत्साहन स्कीम लागू की गई थी।

7. वर्ष 1990–91 के दौरान समय-बद्ध उपकेन्द्र सुविधाओं सहित 400 के०वी० की 4725 सर्किट किलोमीटर और 220 के०वी० की 2489 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों का निर्माण कार्य पूरा किया गया। दिल्ली तथा अन्य पड़ोसी क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार करने के लिए रिहन्द-दादरी एच०वी०डी०सी० लाइन हाल ही में चालू की गई है। ताकि सिंगरौली-रिहन्द काम्प्लैक्स से विद्युत प्राप्त की जा सके।

8. देश के लिए 1991–92 के दौरान 193 बिलियन यूनिट (कोयला आधारित विद्युत उत्पादन) विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसकी तुलना में कोयले की आवश्यकता 146 मीटरी टन (7 मीटरी टन के भंडार समेत) होने का अनुमान लगाया गया है। तथापि कोयला सप्लाई की वर्तमान प्रवृत्ति के अनुसार वर्ष के दौरान कुल मिलाकर कोयले की उपलब्धता लगभग 130 मीटरिक टन होने की आशा है जोकि 180 बिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन

(श्री सुरेंद्रजी। सिंह अहलूवालिया)

के लिए पर्याप्त होगा जबकि लक्ष्य 193 बिलियन यूनिट का है ।

9. माननीय सदस्यगण इस बात से सहमत होंगे कि कुल मिलाकर विद्युत की उपलब्धता में पर्याप्त सुधार हुआ है । तथापि कुछ राज्य अभी भी विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं । इसका मुख्य कारण इनके अपने ताप विद्युत केन्द्रों का कार्यनिष्पादन संतोषजनक न होना है । मैं, माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि राज्यों की विद्युत संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किए जाने में सहायता करने हेतु सभी संभव प्रयास किए जाएंगे और जहां तक संभव होगा उनकी विद्युत की इष्टतम मांग की पूर्ति की जाएगी ।

10. माननीय सदस्य इस बात से भी सहमत होंगे कि पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के साथ-साथ नए नवीकरणी ऊर्जा स्रोतों के विकास एवं समपयोजन से भी देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता संबंधी कमी को पूरा किए जाने में सहायता मिलेगी । ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोतों की आयोजना एवं कार्यान्वयन के प्रति काफ़ी अधिक उत्साह दर्शाया गया है । अपरम्परिक ऊर्जा स्रोतों से संबंधित कार्यक्रमों के फ़लस्वरूप न केवल विकेन्द्रित रूप से ऊर्जा उपलब्ध होती है बल्कि इससे वनरोपण, पर्यावरणीय सुधार, उर्जा संरक्षण, रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य-विज्ञान का स्तर बढ़ाने, समाज एवं महिलाओं के कल्याण, कृषि के लिए और पीने के लिए पानी उपलब्ध कराने तथा बायो-उर्वरक उत्पादन में भी प्रत्यक्ष रूप से सहायता मिलती है । इन कार्यक्रमों से एक वैज्ञानिक भावना और आत्म निर्भरता की मनोवृत्ति का विकास होता है और जिसके परिणाम स्वरूप आयोजन तथा कार्यान्वयन संबंधी प्रक्रियाओं में प्रारंभिक स्तर से ही आम आदमी की अधिक सहभागिता उपलब्ध होती है । सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी से संबंधित अनेक कार्यक्रम हाथ में लिए गए थे । इनसे प्राप्त अनुभवों के आधार पर आठवीं योजना के दौरान अल्पकालिक एवं दीर्घ-कालिक आधार पर इन प्रौद्योगिकियों को अपनाए जाने हेतु और उपाए किए जाएंगे ।

श्री सुरेंद्रजी। सिंह अहलूवालिया : उपसभापति महोदय,, मंत्री जी ने बड़ा ही विस्तृत वक्तव्य रखा और उसके माध्यम से विद्युत विभाग के उज्जवल वर्तमान और उज्जवल भविष्य के बारे में बखान किया। पर अफ़सोस की बात है कि आज भारतवर्ष का हर एक नागरिक यह महसस कर रहा है कि भारत में जो ऊर्जा उत्पादन है उसमें बहुत अवरुद्धता हुई है और जिस वक्त ऊर्जा की जरूरत है, बिजली की जरूरत है उस वक्त वह उस व्यक्ति को उस उपभोक्ता को उपलब्ध नहीं होती है । चाहे वह एक डाक्टर हो उसने आपरेशन थियेटर में एक पेशंट को बैठाकर रखा हो, उस वक्त बिजली गुल हो जाती है, या उद्योगपति हो जिसने इंडक्शियल फ़र्नेस प्लान की हो और लोहा या किसी धातु को मेल्ट करने की सोच रहा हो कि उसी वक्त बिजली गुल हो जाती है । चाहे वह आईसक्रीम बेचने वाला अपने आईसक्रीम प्लांट में सारा पानी डाल कर और सारे मसाले डाल कर आईसक्रीम बनाने की तैयारी कर रहा होता है और चाहे वह किसानों के लिए कोल्ड-स्टोरेज हो, वहां पर भी ऊर्जा उपलब्ध नहीं है ।

आखिर इतने पैसे खर्च होने के बावजद, इतना इनवेस्टमेंट होने के बावजद इतने बड़े-बड़े प्लांट लगने के बावजूद यह ऊर्जा जाती कहां है? यह ऊर्जा लोगों तक उपभोक्ताओं तक क्यों नहीं पहुंचती? तो यह मेरे फ़िगर्ज नहीं हैं, यह सरकारी फ़िगर हैं और सरकार खुद स्वीकार करेगी इन बातों को कि सब से पहले अगर हम लें, तो यह कहते हैं कि हमारा ट्रांसमिशन लास जो है वह 21.5 परसट है । पहले अगर देखा जाए तो इनके प्लांट की केपेसिटी यटिलाईजेशन जो है, जो प्लांट लोड फ़क्टर है, वह एवरेज आता है 56.4 परसट या 57 परसेंट तक पहुंचता है। उसके ऊपर नहीं पहुंचता है ।

उसके बाद अगर ट्रांसमिशन लास की बात करते है, तो 21.5 परसेंट ट्रांसमिशन लास है । महोदया, यह ट्रांसमिशन लास क्या है? यह ट्रांसमिशन लास सरासर धोखाधड़ी है, चोरी है और वह चोरी मिलीभगत से है और लोगों ने गलत कनेक्शन लगाये हुए है । आज के अखबारों में सब ने पढ़ा होगा कि दिल्ली में बहुत बिजली चोर पकड़े गये हैं ।

श्री कल्पनाथराय: वह हमने किया है।

श्री सुरेन्द्र जीत सिंह अहलुवालिया: वह कल्पनाथ राय जी की कृपा होगी । इन्होंने जरा जाकर थानेदारों को धमकाया होगा, डंडा दिखाया होगा कि वह चोर पकड़े गये । पर यह 21.5 परसेंट में सिर्फ़ चार या पांच हजार चोरी नहीं हैं और सिर्फ़ दिल्ली में ही नहीं हैं, यह पूरे भारत में चोर हैं और पूरे भारत में यह जो विद्युत की चोरी कर रहे हैं, यह सिर्फ़ विद्युत की चोरी नहीं है, यह हमारी राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय संपदा की चोरी है, यह हमारी राष्ट्रीय संपत्ति की चोरी है, जिसके रक्षक हरेक सरकारी अफ़सर और मेम्बर आफ़ पार्लियामेंट हैं । ...(**व्यवधान**)

श्री बोरेन जे शाह (महाराष्ट्र): और अपने बजट में...(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य: इसमें पूंजीपति ...(**व्यवधान**)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: मैं कहता हूं कि इसमें सबश शामिल हैं । ...(**व्यवधान**)

उपसभापति: आप अपना भाषण बोलिये।

श्री शांति त्यागी (उत्तर प्रदेश): इसमें टाटा, बिरला पूंजीपति..(**व्यवधान**)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: हमारे मित्र, शांति त्यागी जी, कह रहे हैं उद्योगपति--मने तो नहीं कहा कि जूता, चप्पल सिलाई करने वाला चोरी कर रहा है । यह तो समझने की बात है कि चोरी कौन कर सकता है । जिसके पास विद्युत की कुछ मशीनें होंगी, कुछ होगा, तो वही चोरी करेगा और दूसरा कौन करेगा । जिसके घर में खाने को ही नहीं हैं, हचीया नहीं है, वह क्या चोरी करेगा ।

तो, उपसभापति जी, इस पर ध्यान देने की जरूरत है । अब अगर हम देखें कि कोयले का उत्पादन साथ में जोड़ें कि कोयला का उत्पादन कितना है और कोयला कितना है, बड़े अफसोस की बात हैं कि फरवरी, 1990 तक यह इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड एक तरफ तो यह चोरी करवाते हैं, ट्रांसमिशन लास और केपेसिटी यूटिलाईजेशन नहीं है, काम नहीं करते और उसके ऊपर उनका बकाया कितना है, कायले का बिल, 1,914 करोड़ रुपया कोयला विभाग को इलैक्ट्रिसिटी बोर्डस ने देना है । और इनकी गलती के कारण इनके यहां जो नकसान हो रहा है, उसके साथ कोयला विभाग में भी नुकसान हो रहा है और राष्ट्रीयकरण से पहले जो कोयला 50 रुपये टन मिलता था, वह आज 750 रुपये पर टन हमें दिल्ली मे खरीदना पड़ता हैं ।

तो हम खड़े कहां हैं? हमने इस मुल्क को किधर ले जाने की कोशिश की थी और यह किधर जा रहा है ।

महोदया, कल मेरी एक सीनियर इलैक्ट्रिकल इंजीनियर से बहस हो रही थी। मैंने उनसे साधारण सा प्रश्न किया, साहब, आपके बहुत से थर्मल पावर प्लांट्स हैं और रेणुसागर में एक बिरला जी का प्लांट हैं । उसकी केपेसिटी यूटिलाईजेशन 110 परसेंट है और आपकी केपेसिटी यूटिलाईजेशन 37 परसेंट है, क्यों? मुझे यह समझाइये ।

तो उन्होंने मुझे समझाया, कहने लगे साहब, बिरला जी ने एक अलग सेपेरेट बायलर लगाया हुआ है, एक स्टैंडबाई बायलर लगाया हुआ हैं ।

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

तो मैंने कहा साहब, आपको स्टैंडबाई बायलर लगाने में, जहां आपने चार बायलर लगाए हुए हैं, वहां पांचवां बायलर लगाने में किसने रोका था, किस डाक्टर ने मना किया था ? अगर इस चीज को चलाना है इट इज ए कंटीन्यूअस प्रासेस तो आपको एक अलग स्टैंडबाय बायलर लगाने से किसने रोका है, जब यह करोड़ों रुपये के हैं। आज के हिसाब से एक मेगावाट का प्लांट लगाने के लिए 3.3 करोड़ रुपये की जरूरत है और आज हमारे कन्ट्री में 38000 मेगावाट जो कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में पास हो जाना चाहिए था क्योंकि जिसका इफैक्ट हमें जाकर 9वीं पंचवर्षीय योजना में पड़ेगा उसके बारे में सोचना था। जब इनके विभाग ने तो मांग की कि यह दुर्भाग्य है कि पिछले दो साल जो सरकार यहां रही उसे तो साल के अन्दर आर प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन बदले गए और कुछ प्लानिंग कमीशन ने आज तक डिसाइड नहीं किया। यह हमारा अपना ऐजंप्शन है, प्रिजंप्शन है, हम कह रहे हैं और मंत्री जी भी कह रहे हैं कि हमें 26000 मेगावाट की परमिशन शायद मिल जाती है और 2200 मेगावाट की दूसरे तरह से फिर भी वहांपर 10 हजार मेगावाट का गैप रह जाता है। महोदया, दस हजार मेगावाट का फर्क कितना पड़ेगा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आज तो हम सोच रहे हैं कि यहां दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी में जब यह बात कही जा रही है कि आप अपने कूलर मत चलाइये, एअर कंडीशनर मत चलाइए, आप ठंडे पानी की मशीनें और फ्रिज मत चलाइये तब गांव और देहात में क्या हो रहा होगा ? डिस्ट्रक्ट हैडक्वार्टर्ज में क्या हो रहा होगा, यह सोचने की जरूरत है ?

महोदया, मैं बिहार से आता हूं और मेरा और हमारे राज्य का बड़ा दुर्भाग्य है कि सब से कम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारे राज्य में होती है और सब से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन लासेज भी वहीं होते हैं, पर दुःख इस बात का है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आन्ध्र प्रदेश में ज्यादा है, महाराष्ट्र में ज्यादा है और राजस्थान तथा गुजरात में ज्यादा है, वहां भी ट्रांसमिशन लास है और सारे हिसाब से अगर एवरेज ट्रांसमिशन लास पर आएं तो वह साढ़े इक्कीस प्रतिशत आ जाते हैं। महोदया, हम अगर इसको गौर से देखें ऊर्जा एक इसी तरह है जिस तरह एक आदमी का हृदय है। हमारे देश के लिए ऊर्जा हृदय का काम करती है। हृदय की गति जिस तरह बंद हो जाए तो हमारे ब्रेन से लेकर पैर के नाखून तक ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है और आदमी मर जाता है। जब देश की ऊर्जा की उत्पत्ति बंद हो जाए, जबकि देश की ऊर्जा का उत्पादन बंद हो जाए या कम हो जाए तो वह एंजायनिंग पेशेंट है। उसकी बायपास सर्जरी करने की जरूरत है और उस बायपास सर्जरी के लिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को अनुरोध है कि उसका कोई रास्ता निकालें कि आखिर इतने प्लांट्स लगाने के बावजूद आज हमें यह बात क्यों कहनी पड़ रही है और क्यों सोचना पड़ रहा है? अब आप देखिए महोदया, 28 फरवरी, 1990 तक उत्तर प्रदेश के इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने 284.94 करोड़ रुपये कोयला विभाग का देना है। अब यह लास में चल रहे हैं। अभी सुबह सवेरे आज पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का यह बजट पेश कर रहे थे और पंजाब इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड जो कि आलरेडी करीब 91 परसेंट रेवेन्यू लास पर चल रहा है जिसके बारे में अभी इन्होंने अपनी मांगें रखी हैं। एस्टीमेटिड रेवेन्यू एक्सपेंडीचर और एनुअल डिफिसिट करीब 693 करोड़ रुपये का है और टोटल स्टेट को करीब 900 या 95 करोड़ रुपया मिलता है जिसमें 693 करोड़ का डेफिसिट लास सिर्फ पी०एस०ई०बी० में है। उपसभापति महोदया, अगर हम इस पर विचार करने बैठें और देखें कि जो मेन चीज है जिसमें हमने किस तरह से इसको गलत रास्ते पर लिया है। अब किसी एक इंजीनियर से यह पूछिए कि साहब, पीक लोड होता है और आपका सरप्लस टाईम कौन सा है तो यह विद्युत विभाग वास्तव में इसके साथ में जुड़ा होना चाहिए आपका उद्योग विभाग भी और उद्योग विभाग तो रोज यहां पर बड़े-बड़े विज्ञापन निकाले जा रहे हैं कि एक खिड़की

के माध्यम से ही राजस्थान गवर्नमेंट लाइसेंस देगी, विद्युत देगी, ऋण देगी, सब कुछ देगी । यह सब कुछ मिल जाता है, पर अगर पूछिए कि, साहब मैं दिन के वक्त 8 बजे से 4 बजे की शिफ्ट में इंडेक्शन फर्नेस चलाना चाहता हूं, जहां मेटल डायकास्टिंग का काम करना चाहता हूं, आप क्या मुझे विद्युत दे सकेंगे ? आपके पास सरप्लस है ? तो मैं कारखाना तो लगा लूंगा, लेकिन विद्युत नहीं मिलेगी और मेरा कारखाना बंद रहेगा, अल्टीमेटली वह रुग्ण होगा और ऑक्सन होगा । तो इसमें जो सिस-मैनेजमेंट है, वह डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम की है । जिस वक्त हमारा पीक शिफ्ट ओवर है, उस वक्त किस तरह की इंडस्ट्री को डिस्ट्रीब्यूशन हो और किस वक्त हमारे पास सरप्लस पावर है, उस वक्त किस तरह की इंडस्ट्री को डिस्ट्रीब्यूशन हो और उसी टाइम के लिए इंडस्ट्री को लायसेंस मिले, यह डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत है ।

अब किसानों की बात आती है । अभी मानसून के बारे में आप कह रहे थे कि इस बार मानसून की अवस्था खराब है और हो सकता है इसलिए और मुसीबतों का सामना करना पड़े ।

उपसभापति : मि० अहलुवालिया आप कितना समय लेंगे ?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैडम अभी तो बड़ा टाइम है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have other names.

कॉलिंग अटेंशन में क्योंकि पाइंटेड क्युश्चेंस होते हैं तो अगर आप अपनी भूमिका बना चुके हों तो सवाल पूछिए—
—pointed questions, so that we will keep the same 'Parampara' otherwise it will be come a debate and the Minister won't have time to answer.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैडम, मैं क्युश्चंस पर आ रहा हूं । अभी इन्होंने बताया कि मानसून के आने में विलंब होने तथा सामान्य से कम वर्षा होने के कारण कृषि क्षेत्र में विद्युत की मांग में काफी वृद्धि हुई है । उपाध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके से आते हैं, इसलिए वे घाघ की वाणी को अच्छी तरह से जानते होंगे । घाघ ने अपनी वाणी में जिसको हमारे गांव के पंडित अपनी एफिमरी में लिखते हैं, "आगे मंगल पीछे धास, वर्षा हो ओस समान ।" यह प्रिडिक्शन आज का नहीं है । यह घाघ की वाणी कई सौ साल पहले से लिखी हुई है । हमारे मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले आजकल टी०वी० में सैटेलाइट की फोटो नहीं दिखाते क्योंकि उनकी प्रिडिक्शन फेल हो गयी है । उन्होंने कहा था कि वर्षा बहुत अच्छी होगी । तो यह "आगे मंगल पीछे धास, वर्षा हो ओस समान" के अनुसार इस साल यह जो आगे आगे मंगल चल रहा है और पीछे पीछे सूर्य देवता चल रहे हैं, तो वह जब तक चलते रहेंगे बरिस ओस के समान होगी । यह सर्वविदित है और गांवों में लोग मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एनाउंसमेंट का इंतजार नहीं करते हैं, वह गांव के पंडितजी से पत्रिका देखने को कहते हैं और पूछते हैं कि रोहिणी नक्षत्र या आर्द्रा नक्षत्र कब लगने वाला है और कब बरिस होगी ताकि हम हल, बैल और बीज तैयार करें । अब विचार यह करना है कि इस वक्त जब ओस समान होनी है तो क्या हो । इसकी तैयारी हमें करनी है कि कैसे हम इसे किसानों को पहुंचा सकें । पर किसानों के लिए भी हम बड़े-बड़े पॉपुलिस्ट स्लोगन ले लेते है

अब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने सबसे बड़ी स्टेट उत्तरप्रदेश में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के बनने के पहले एक डिमांड लिख दी कि, साहब अगर हम पावर में आए तो किसानों के जितने भी विद्युत के बिल हैं, वह माफ कर दिए जाएंगे । सारे माफ कर दिए जाएंगे और उसके ऊपर तमिलनाडु में डी०एम०के० के करुणनिधि जी गए जिन्होंने कहा कि, साहब हम किसी भी किसान को

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया] कोई भी एग्रीकल्चर के लिए फुल इंसेंटिव देंगे और करीब-करीब मुफ्त के दाम पर बिजली देंगे । उपाध्यक्ष महोदय, अगर उपभोक्ताओं को हम इसी तरह बिजली बांटते रहे तो एक तो ट्रांसमिशन लॉस्स होगा, ऊपर से टोटल लॉस और यह जो बाकी बचा है, यह लॉस होगा । आखिर जो बिल देकर बिजली खरीदना चाहते हैं, उनके लिए क्या बचेगा, यह भी सोचने की जरूरत है । ...(व्यवधान)... टैरिफ बढाना चाहते हैं...टैरिफ तो पंजाब में रु. 1.3 पर यूनिट और यहां 2.3 है, फर्क तो है । वहां लोसेस चल रहे हैं और वह कह रहे हैं कि हमें टैरिफ बढाने की परमीशन दी जाए ।

उपसभापति : अब आप अपना भाषण करने की कृपा करें ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैडम मैं कर रहा हूं ।

उपसभापति महोदया, जब हम इस वक्त इन चीजों पर गौर फरमा रहे हैं कि देश के अंदर कार्य करना है और देश को सही रास्ते पर लाना है तो सबसे बड़ी जरूरी चीज है ऊर्जा का उत्पादन बढाने के लिए हमें कोई न कोई रास्ता निकालना है । सी० पी०एम जैसी सरकार ने बंगाल में फैसला कर लिया, उनके बोर्ड आफ डायरेक्टर ने, उनके एस० ई० बी० के डायरेक्टर, मिस्टर संजीव गोयनका ने कहा है कि साहब, अल्टीमेटली हमें प्राइवेटाइजेशन पर जाना पड़ेगा और कुछ इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड और इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट प्राइवेट कंपनियों को देने पड़ेंगे क्योंकि जब तक यह कंपटीशन नहीं होगा तब तक इसका प्रोपर केपेसिटी युटिलाइजेशन नहीं होगा ।

उपसभापति महोदया, मेरा यह मानना है और मेरी यह मांग है कि आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि एक कमेटी बनाइए, जो इसका सर्वे करे कि आखिर एटी टेक्नोलोजी थर्मल पावर प्लांट की और वह थर्मल पावर प्लांट की टेक्नोलोजी जो बिहार में चलती है उसमें प्रोडक्शन कम है, फिर आन्ध्रप्रदेश में चलती है तो उसमें प्रोडक्शन ज्यादा है, जब वह महाराष्ट्र में चलती है तो ज्यादा है, फिर उत्तरप्रदेश में चलती है तो उसमें प्रोडक्शन कम है और जब बंगाल में चलती है तो वहां मिनल हो जाता है, आखिर कारण क्या है ? इसके पीछे बहुत से कारण हैं और इन कारणों का पता लगाना बहुत जरूरी है और पता लगाकर किसी निष्कर्ष पर आना जरूरी है। एक तरफ हम सैल्फ रिलाएन्स की बात करते हैं, अपने देश को इक्कीसवीं सदी में ले जाने की बात करते हैं, किन्तु यदि हम देश की ऊर्जा ही नहीं दे सके तो हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे ?

उपसभापति महोदया, इधर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया कि एअर-कंडीशनर मत चलाइए । मैं आपकी जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि हर साल देश में लगभग दो लाख एअर-कंडीशनर बनते हैं और दो लाख एअर-कंडीशनर बिकते हैं । आपमें एक तरफ तो ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता नहीं है और दूसरी तरफ आप ऐसी चीजों का उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें ऊर्जा का उपयोग होता है, जिसका रा-मेटेरियल ऊर्जा है । एअर-कंडीशनर का उत्पादन आप बंद नहीं कर रहे हैं, टी०वी०, वी०सी०आर०, वाशिंग-मशीन का उत्पादन आप बंद नहीं कर रहे हैं, जो कि लग्जरी आइटम हैं, जिनको हमारा देश एफोर्ड नहीं कर सकता है । पर लग्जरी होने के बावजूद भी इन चीजों के उत्पादन पर कोई रोक नहीं है और दूसरी तरफ आप में ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने की क्षमता नहीं है ।

उपसभापति महोदया, मुझे याद आता है एक अपना छोटा सा तुका, कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सब कुछ होते हुए, सारे प्लांट होते हुए, सारे कंपोनेण्टस होते हुए और सारी सुविधाएं होते हुए भी हमें जब ऊर्जा नहीं मिलती है तो मेरे मन में आता है कि मैं भी कहूं सड़क पर खड़े होकर, कि—"रघुपति राघव राजा राम, पूरा पैसा जीरो काम" क्योंकि यह राम-भरोसे ही चल रहा है, राम-राज्य की कल्पनाएं चल रही हैं। तो "रघुपति राघव राजा राम, पूरा पैसा जीरो काम", काम कुछ नहीं करना है, बिल के लिए धमकी आ जाती है कि शाम तक बिल अदा नहीं हुआ तो कनेक्शन काट दिया जाएगा, चाहे कनेक्शन एक बल्ब का ही क्यों न हो । तो पैसे के लिए तो तैयार हैं । अब जो कनेक्शन काटने आता है वह भी पैसा मांगता है, जो कनेक्शन जोड़ने

आता है वह भी पैसा मांगता है। अगर इस मुल्क को इस ऊर्जा संकट से बचाना है तो इस नारे में सुधार लाना होगा। इस नारे में सुधार लाने के लिए मानसिक चरित्र में सुधार लाने की जरूरत है। मंत्री महोदय यहां अकेले बैठकर सुधार ला सकेंगे, इससे मैं डरता हूं। मगर मेरा कहना है कि इस बारे में कुछ उपाय ढूंढें। अगर मंत्री महोदय जरूरत समझते हैं सर्वे करने के बाद कि सरकार को छोड़कर क्योंकि कारपोरेशन तो बहुत बन गए हैं, सरकार को छोड़कर कंपटीशन लाकर अगर कोई प्राईवेट कंपनी आकर इस कोसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ा सकती है तो वैसी प्राइवेट कंपनियों को इन्वाइट करना होगा। जहां तक मेरी जानकारी है बारह प्राइवेट कंपनियों की एप्लीकेशन मंत्रालय के पास पेंडिंग पड़ी हैं। सरकार उनके बारे में क्या सोच रही है और किस तरह प्लांट यहां लाने जा रही है, जरा इस बारे में मंत्री महोदय बताएं।

उपसभापति महोदया, दूसरा मैं यह कहना चाहूंगा कि एक बड़ी अजीब बात है, जो दूसरे विभागों से भी जुड़ी हुई है। कहीं-कहीं पावर प्लांट, जैसे राजस्थान में हुआ कि बाबा आमटे ने वहां जाकर उसको रुकवा दिया। यह बाबा आमटे रुकवा रहे हैं, एन्वायरमेंट के नाम से कह रहे हैं कि साहब, घडियाल मर जाएगा, कोई जंगल सड़ जाएगा, और इस तरह पावर-प्लांट रोके जा रहे हैं। 1.00 PM, तो इन पर भी रोक लगाने की जरूरत है। उपसभापति महोदया, इसके साथ-साथ बड़े आश्चर्य की बात है कि एक नया पावर प्लांट आप इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो 25 प्रतिशत ड्यूटी लगती है और एक पुराने प्लांट का मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं तो उसमें 125 प्रतिशत ड्यूटी लगती है, इस पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। महोदया, आखिर क्या कारण है और से हमारे सेल्फ रिलायन्स के रास्ते में अड़चने डाली जा रही हैं और इसके अंदर जो लूप-होल्स हैं, इन सारी चीजों का विश्लेषण करने के लिए मैं एक कमेटी की मांग करता हूं और उस कमेटी के माध्यम से अविलम्ब एक ऐसी कमेटी बैठाई जाए जो तीन महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करे कि इस देश में ऊर्जा सुधार कैसे लाया जा सकता है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I want to remind that we are discussing calling attention and not a debate on any motion. So, please confine yourself to questions.

SHRI VIREN J. SHAH: Madam, upto what time are you continuing?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I would like to finish it at 1.30 p.m. If everybody ask questions it is very much possible.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): There is a difference between a discussion on a statement that the Minister gives and the questions that the Members put. That is not a statement from a Minister. We are not expected to elicit information by asking questions.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think, Mr. Gurudas Das Gupta, for a very long long time we have not had calling attention. All of you have forgotten.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: We are all in the House for a pretty long time. We know the procedure and practice.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The thing is that if it is a discussion, I will permit according to time. If it is calling attention, we have a very important Bill. So, let us... (*Interruptions*).

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: But Chair should also describe the demarcation line between eliciting information and participation in the discussion on calling attention.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is no discussion. It is only questions. That is the difference I want to tell you. I want to correct that Mr. Ahluwalia was the first speaker. He called the attention of the Minister. So, he has given the description of

[The Deputy Chairman]

what he wants to say in detail and the rest of the Members can ask on what Mr. Ahluwalia said.

SHRI VIREN J. SHAH: I think a lot of things left by Mr. Ahluwalia can be carried on by Mr. Gurudas Das Gupta.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, the point is we have a statement from Minister of State of the Ministry of Energy. Accidentally, the name of the Minister of State of Energy is Mr. Kalp Nath Rai. It seems that the statement is only *Kalpana* of Kalp Nath Rai. Why? In the second paragraph of the statement, it is said that "I would like to assure the House that all possible measures are being taken to augment the availability of power". Is it true? Is it true that the Government is taking all possible steps to augment power? Secondly, Madam, on page 4 it has been stated that there has been a considerable improvement in the overall availability of power. It cannot be except in the imagination of the Minister holding the portfolio of Energy and having the name Kalp Nath Rai. Therefore, I say

कल्पनाथराय जी की कल्पना के ऊपर हम लोग डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।

When the Minister says so only today there is a news item in the newspaper. What does it say? It says about the condition in up from where the Minister has been elected this time. In UP the State Electricity Board has discontinued the supply of power to IDPL on 28th June and the State Electricity Board has given no cause. Why discontinuation of power has been ordered? As a result the manufacture of life saving drugs has been discontinued . If this is a sign of improvement or if this is a sign of sincerity on the part of the Government to augment power supply, I have no quarrel with the Minister. Secondly, Madam, there is news today that Coal India has cut down coal supply by 30 per cent to the thermal units not of West Bengal but of the State to which the Minister belongs. Thirty per cent of the coal supply has been discontinued in U.P. as a result there is a serious shortfall in the supply of power which, in turn, is affecting coal production. This is a vicious circle. Power supply is being discontinued arbitrarily and coal supply is being discontinued which is leading to disruption in power supply. That is the latest situation in Uttar Pradesh from where the Minister has been elected.

Let me come to the State of West Bengal. It is in the State of West Bengal where within a span of one year that is, on 25th June, 1990 and for the second time in July 1991, there was a total collapse of the eastern grid I hope the Minister knows about the eastern grid. Eastern grid has collapsed and as a result of the collapse, the entire industrial economy in West Bengal came to a shut down. It is not because of shortfall in power supply. Minister does not know. Why was there a collapse of the grid? There was this collapse because there was disruption or disturbance in the line between Chukha and Farakka. Maintenance of this line is the responsibility of NHPC, not of the State Government, but of a public sector unit under the Department of Energy of the Government of India, and as a result of this disruption, there was a collapse and as a result of this collapse the entire State of West Bengal and Bihar had a blackout. This happened for the second time. It also occurred at least one year back, and there was a demand from the State of West Bengal that there should be an enquiry as to why there was disturbance in the line between Farakka and Chukha. I don't know if any enquiry was conducted. At least the factor that led to the disturbance has not been removed. This is the performance of the Department of Energy. The factors responsible for the disturbance could not be removed even within a span of one year.

My next question to the Minister is, despite the claim that everything is being done to augment power supply, thermal power plant in Kolaghat had run short of stock of coal for 15 days. There was no power supply from that particular power station. It is Coal India which did not supply coal to this unit. Now, who is going to haul up Coal India for not maintaining uninterrupted supply of coal to Kolaghat? Then, even if coal is supplied to Kolaghat, there is disruption again because of boulders. I think the Minister knows what is boulder. Boulder is not used for production of power. As a result, there is also disruption. Therefore, due to the irresponsible attitude of Coal India for which Government of India is responsible, power supply in West Bengal is suffering seriously.

I hope the Minister knows that there is one unit in Durgapur, DPL. It had to close down two of its machines because there was no coal. As you now, Durgapur is situated on the pithead of collieries. Even there, coal supply cannot be maintained by the Government. Only today's report in the newspaper says that one of the States having the chronic problem of power shortage is the State of Bihar. It is in Bihar that a number of projects are lying pending with the Government, with the Department of Energy, over years. You take time to clear the files but you do not take time to augment generation of electricity. That is your claim which we have to believe. The Minister says that in the 8th Five Year Plan, the total additional generation will be to the extent of 38,000 MW. Only that day, the paper that was submitted by the Ministry of Energy in a conference on power generation that took place in 1990, said that at least 17,000 MW will be the shortfall so far as the targtt of the 8th Plan is concerned. Why, 17,000 MW? Because there is a resource crunch. Rs. 50,000 crores will be required more and as a result of the lack of availability of funds, they will not be in a position to generate at least 17,000 MW of electricity that the Government claims will be the additional generation for the next Five-Year Plan. Therefore, there is always a gap between the promise and the performance. Even, on the question of promise, the Energy Department says that it will not be able to produce at least 17,000 MW because there is no money. I hope that the Minister would speak on this.

Then, Madam, everybody knows that the proper generation and supply of power depends on a proper mix of hydel and thermal power generations. That is the normal condition for maintaining the power supply and ensuring that there is no disruption. In our country, only 14 percent of hydel power potential has been exploited by the Government. After so many years of freedom, it is only 14 per cent. According to the specialists' report, the total hydel potential of the country is 84,000 MW. Out of this, only 14 percent has been exploited. Even after exploiting so little of the hydel power potential, how can the Government expects this House to believe that everything is being done to augment the power suply in the country? Madam, in this respect, I refer to the problem of West Bengal. In West Bengal we are suffering from the shortage of power not because there is a total mismanagement but because the Central Government is not sanctioning a number of projects concerning hydel generation in that State. At least in Farakka, there is a proposal to have a hydel power station and the Government of India is sitting over that and what is the result? The result is that there is a swing of frequency and as a result of the swing of frequency arising out of an imbalance in the mix of hydel and thermal power generation, there is an occasional disturbance in the Eastern grid and this occasional disturbance in the Eastern grid is leading to power cuts. The power cut in West Bengal is not always due to the shortfall in the generation of power, but, it is because of the dis-

[Shri Gurudas Das Gupta]
turbance that has been created in the grid of the eastern part and the disturbance in the Eastern grid is taking place because of this imbalance. There is no effort on the part of the Government of India to remove this imbalance. While the imbalance continues to disturb the uninterrupted supply of power the Government of India is taking time over a proposal concerning construction and commissioning of a hydel power project in Farakka.

Madam, I have another complaint. There is a price discrimination that has been practised by the NTPC. If West Bengal is forced to pay 80 paise per unit to the NTPC, then, what is the reason that the northern States will be allowed to purchase power from the NTPC at the rate of 47 paise per unit? If Farakka power is costly to West Bengal why the Singarauli power is cheap to the northern States? Why this discrimination of prices that this Government and the Ministry of Energy are practising? Therefore, Madam, let us not live in the wonderful world of imagination and let us all believe that there is a serious power shortage, and this power shortage arises out of stagnant investment, for power generation in the successive Five-Year Plans. Madam, in the first Five-Year Plan, only 19 per cent was the investment for electricity generation of the total outlay for the public sector undertakings. Even in the last Five Year Plan, the total investment for power was only 19 per cent. This stagnating investment rate is one of the reasons as to why India is lagging behind in power. You are borrowing money from World Bank. You are liberalising the economy. You are going out of your way to satisfy the World Bank. We shall have discussion on this some other day. You can bring money from outside for the rejuvenation of the Indian economy, but can you bring power from outside? Therefore, the external help or the external dole that you are begging shall be of no use. The economy shall not survive if there is no enough additional generation of power. Additional generation of power cannot take place without increasing investments. For increasing the power capacity in the short period, we need to set up not only thermal projects, but we need to set up hydel and gas projects also. They take less time for commissioning. For setting up gas-based power projects, why don't you go in for construction of pipelines from the Bombay High? You have built a pipeline from the Bombay High to U.P. I do not grudge. Let UP have the lion's share. But while giving U.P., a part of the gas from the Bombay High, what prevents you from constructing a number of pipelines from the Bombay High to the southern part of the country and to the eastern part of the country?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Gurudas Das Gupta, you have asked enough questions. Please take your seat now.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, I am on points. The point is, there is an acute shortage of power. There is not only acute shortage, but there is lack of proper planning. There is also lack of co-ordination between the different agencies involved in the production and generation of power. I am only pointing this out. My question is, while gas is being flared from the Bombay High in the grand city of Bombay to which you belong, why does not the Government lay a number of pipelines to supply gas to the other parts of the country which could be used for the commissioning of gas turbines? I surely believe that the commissioning of the gas turbines would be useful for augmenting the power generating in a short period of time. Therefore, Madam, I say, let the Minister not live in his own make-believe world. Let the Minister come to the ground realities and face the situation with the co-operation of all. I suggest not only a Parliamentary delegation or a Parliamentary Committee. I think he has to initiate

steps to ensure that the plant load factor of the different thermal units its improved. Therefore, I suggest that he should call a conference of the trade unions connected with the power sector. Take their co-operation. Mr. Kalp Nath Rai, as an individual, as a Minister, you can initiate the policies. But for the implementation of the policies, you need officers and workers. How you can inspire your officers and workers...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Gurudas Das Gupta, you come to the ground realities and take your seat.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, I suggest that there should be a conference on power to be attended by the trade unions connected with the power sector. In that conference, let there be a proper understanding as to how the working class is willing to help you. The working class is willing to help you, but you are not willing to take their help because, if there is shortage of power, it is not the Minister who losses his job...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let the working class help the Chair first.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, it is because of the shortfall in power generation that there are lot of problems. In U.P., the people are facing a lot of problems. In West Bengal, there is a serious problem in the small-scale industries because of lack of power for which you are responsible. Therefore, please take the help of the workers. Please do not just sit in the Shram Shakti Bhavan. Go to the workers. Speak to them. Call a conference. I am sure, the working class is in a position to help you. It is with their help that we should take steps in the direction of preventing shortfall, improving the functioning of the existing plants and the setting up of new plants so as to ensure that the thermal and hydel potential in the country is exploited. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Gurudas Das Gupta, I think you should also realise the ground reality of constraint of time over here. You should try to co-operate. If the working class is not co-operating with the Chair itself, how can we expect...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, this is about shortage of power. The Minister is powerless. Therefore, I am giving some powerful suggestions.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Put some power into the Chair first. Shri K. K. Birla.

SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA (Rajasthan): Madam Deputy Chairman, deficiency in infrastructure depresses the economic growth. Negligence, mismanagement and bad planning are, in my opinion, crimes against the society. The performance of the power sector in 1990-91 has been very dismal. The plant load factor in 1990-91 was 53.5 per cent. The hon. Minister, Mr. Kalp Nath Rai, has given the figures for 1985-86. But if you take the figure for the preceding year, namely, 1989-90, you find that the plant load factor was 56.5 per cent. In the next year that is in 1990-91, it slided down by 3 per cent, to 53.5 per cent. Madam, the overall shortage in 1990-91 was 11 per cent. This has been the highest in recent years. If you observe the performance of some of the other units in private sector, take for instance the case of Calcutta Electric Supply and compare it with the State Electricity Board. West Bengal, take the case of Rihand power company and compare it with the State Electricity Board in U.P. or take the instance of Tata power companies you will find that there is a big difference so far as the performance is concerned. Owing to poor performance of the State Electricity Boards almost every company in the private sector has installed its own diesel sets. Not only rompanies, even in residential houses people have installed diesel sets. This is a colossal waste of diesel oil and fuel

[Shri Krishna Kumar Birla]

oil which ultimately amounts to a colossal waste of foreign exchange. If power factor is improved which is quite feasible, thousands of crores of rupees will be saved in new plants. Power supply will also improve as a result of that. One per cent improvement in power factor means additional production of 500 megawatt.

We should also go into the reasons for poor power generation and the poor plant maintenance. Mainly this is due to theft; this aspect must be attended to very carefully. But apart from that, there are heavy transmission losses which are very very high indeed. The figures for transmission losses are about 20 to 22 per cent, whereas in foreign countries the figures of transmission losses are 5 to 10 per cent only.

My friend, Shri Ahluwalia has mentioned that this is owing to a lot of theft. Theft is there in almost all sections of the society and the Minister should pay attention to this aspect. Otherwise, whatever power we produce, a large percentage gets wasted.

Talking about power breakdowns, special mention may be made of the experience we had in the Capital in recent times. The performance of DESU unfortunately has been very unsatisfactory. Partly, it might be owing to: Against management by professionals (i) bureaucratic controls, (ii) political interference, (iii) lack of accountability. The result is that Delhi sweats and fumes, taps go dry, citizens suffer. Unless power scenario improves, the country will enter into 21st century with power shortages unmitigated. Side by side, I will plead that as far as the Planning Commission is concerned, they should provide adequate funds. Also we have to improve our capacity utilisation so that we do not throw away our money into drains.

Madam, according to the 8th Plan, working group on Power Sector it is felt that the growth of power would be about 10 per cent. For this, colossal funds will be needed. Major portion of this could be saved if performance is improved and the plant load factor goes up. Side by side, I may also plead that let there be adequate provision of funds from the Planning Commission. I have no doubt that this aspect will receive the attention of Shri Kalp Nath Rai, who is an energetic Minister of Power.

Another cause for worry is the gradual decline of the hydel power generation. The hydel-thermal mix during early 60s was something like 51 : 49, say almost fifty-fifty. At the end of the 8th Plan it is feared that hydel generation may fall to 25 per cent. The ideal hydel thermal mix ratio will be something like 40 : 60. The country has a large hydro potential and the estimation is that the country is in a position to produce something like 600 billion units per year against the present requirement of 384 billion units. Mr. Gurudas Das Gupta has said that only 14 per cent of hydro power is being exploited. My figure shows 18 per cent. Whether 14 per cent or 18 per cent, it shows that only a very small percentage of the total hydro power potential is being exploited.

Madam, side by side, I would also plead that we should tap alternate sources of energy. We all hear about wind power and solar energy. I believe there is a lot of potential as far as biogas is concerned. This is a practical method and a practical measure for our villages and for our households in the villages. This is a renewable source of energy. From organic materials like cowdung and different types of bio-mass, we can produce quite a lot of energy.

Madam, side by side, I would like to state that in foreign countries considerable research is taking place on the generation of energy through hydrogen. We should keep in touch with them and wherever we find that we can adopt their methods, we should try to do so.

Madam, one thing more towards which I would like to draw your attention is that we are not paying proper attention as far as nuclear energy is concerned. Whenever a proposal for nuclear energy is mooted in this country, there is a lot of misgiving regarding the safety of people from radiation hazards. While we should always bear in mind the factor of safety from radiation, we should also realise that modern technology in inbuilt safeguards about emission of radio activity has made such a progress that nowadays these hazards are almost zero and, as a result of that, nuclear power stations the world over are making rapid progress. In Belgium, South Korea and Sweden, over 40 per cent of power generation is nuclear. In Switzerland the figure is 20 per cent. In France it is 50 per cent and it is likely to become 75 per cent. This would show that there is a lot of potential as far as nuclear power is concerned.

Madam, here are a few more suggestions. Firstly, as far as a national power grid is concerned, it should be set up on a comprehensive scale with modern power transmission systems. Then, as far as fuel consumption is concerned, there is a wide disparity in coal consumption, per unit of power consumption of the various power stations. This should be properly studied and we should try to conserve coal wherever we find that wastage is taking place. Then there is a lot of theft which is taking place. Partly, increase in fuel consumption is owing to theft and, partly, owing to indifferent supervision. So what is needed is strict monitoring. Inefficient management and chronic labour trouble are the other factors which need attentions. The genuine demands of labour should always be met but, side by side, after having met those demands, there should be a proper rapport with the labour and there should be proper discipline.

Madam, in spite of these measures, in case the working of power stations does not improve I would plead that steps should be taken towards privatization of the power sector and side by side we should encourage more and more people to come to the power sector.

Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now it is two minutes to 1.30... (*Interruptions*)... If I ask Mr. Balanandon to speak now, he will have to stop within two minutes. So we will adjourn for lunch and then resume the discussion.

The House is adjourned for lunch till 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at twenty-nine minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-four minutes past two of the clock, The Vice-Chairman (Shra M.A. Baby) in the Chair.

SHRI E. BALANANDAN (Kerala): Sir, first of all I say that the Minister's statement has tried to underplay the total situation. The real crisis confronting the country in the power sector has been sought to be underplayed by the Minister. I am sorry for having made such a statement.

Before I go to make some observation. I request the Minister, through you, Sir, that this question of power crisis or power development should be made a subject for a day's discussion in the House, not in the form of a calling Attention motion. A *Suo motu* discussion should be organised in this House so that the country as a whole should know the power situation obtaining in the country. This hon. House will also get an opportunity to help the Government frame a policy so that the crisis can be met. The

[Shri E. Balanandan]

Minister in his statement has stated that in the Eighth Plan we have a programme of producing 38,000 megawatts of power. Originally the Central Elertricity Authority, considering the total requirements during the Eighth Plan, had said that we should have 48,000 megawatts of power during this period, but due to financial constraints it has been reduced to 38,000 megawatts. Afterwards the Planning Commission has said that it should be only 25,000 megawatts. Now, we are told that we are going to produce only 22,000 megawatts. The real story is that the power crisis in the country is in-built in the Plan itself. Delhi is a VIP area and here also we are having the same difficulties. In power availability Delhi is more or less self-sufficient. About Delhi's problems I would come later, but why I am posing this question is to high-light why this power crisis is there. We are told our country is facing a very serious financial cisis. And if we want to get out of this crisis, our people themselves and our country by itself cannot get out of the crisis. Somebody from outside should come and help us. I don't know what type of people will help us. I am only confining myself to electricity crisis. If you don't go by the targets which you had fixed earlier for electricity production after calculating our development needs and if you reduce the target first by ten per cent, again by another ten per cent in the form of a cut by the Planning Commission and another 10 per cent arbitrary cut etc, you will land us in trouble. As somebody has said in this House electricity is the lifeline of the country. If it is cut, then there will not be many industries. Industrial and agricultural development will get affected adversely and there will not be any progress. Yesterday Indian Express reported that Koel Karo project in Bihar, which was envisaged in 1979, is being given up in 1991. Every clearance was given to it and the National Hydro-Electric Development Corporation had been given the responsibility to implement the project. Now these people say it cannot be implemented and it should be given up. This project was envisaged for the development of the backward areas in Bihar. It was urgently needed for the development of the backward areas there and it has now been given up. *Indian Express* has also stated that in Haryana the steel plants and other industries are being closed for want of power. The Chief Minister of the State says "Certainly, power will be given to the agricultural sector." The power is being diverted from industrial sector to agricultural sector. The owners of the steel companies and other factories are asking for power. They are saying that if there is scarcity of power why are you discriminating against industries alone? This is the question which they are asking.

In my State, Kerala, we are having power shortage. There is normally 10 per cent power shortage. We are relying only on hydel power. We have no other source of power. One Kayamkulam project has been sanctioned. For the last two years we have been asking for it. But it is still pending with he Government of India for environmental clearance for the past two years. After twelve years a project is being given up. After two years a project is waiting for environmental clearance. I know the story of another project in Kerala. For the past 12 years it is pending with the Centre. Then, what is it that the Government of India is doing? Are they serious about power development? Now the situation is that instead of 48,000 megawatts, we are going to implement schemes to the extent of 22,000 megawatts. For that also the Government of India is not serious enough to see that they would be taken up in time. Therefore what is to be done? The serious thing to be done is that this power project question should be taken up as a special class. It should be treated separately. The power projects which we want to undertake should be undertaken on a war-footing. If you have a time frame that time frame should be kept.

As I told you, the Koel Karo project when it was designed was expected to cost around Rs. 310 crores. But now it comes to Rs. 1,300 crores. Who is responsible for cost escalation? There is no proper planning. If there is no proper planning, then, the project cannot be completed in time. This department may say okay. The other department may sleep over it. Every clerk will delay it for ten years. This way it goes on. Are you serious about power generation? You are not serious about it. Therefore, I am requesting you that this discussion on calling attention is not sufficient. You have to *suo motu* propose a discussion in this House obout the total power situation in the country and remedial measures thereon. The House may find out where we will be able to help you to get the clearance of the projects, to get the finance for the projects which you want to implement. This is my first submission.

Secondly, India is a vast country having enough resources. Our hydel resources are more than 80,000 megawatts but we have tapped less than 15 per cent of it. The Planning Commission as well as the CEA have said that the ratio between hydel and thermal should be 40:60. What are you doing about it? Today, you see that our trains are running with coal. We are having coal shortage. We are importing coal from Australia. If you generate enough electric power you can run the trains with electricity instead of diesel and you can save a lot of money for the country. Therefore, electricity generation has to be given the first priority and for that the generation of hydel capacity needs to be emphasised. The cost of hydel power ranges from Re.0.30 to Re. 1. The cost of coal-based power ranges from Rs. 3 to Rs. 3.50. If you look into the economics also, you will find hydel power better than other kinds of power. Not only that we are facing a lot of difficulties with coal-based power generation. The power generation deficiency can be met only through hydel projects.

There is another point. Today, another remedy is suggested. It is suggested the power sector can be given to the private sector. Requests have been made by Ministers and big leaders for privatisation of power sector. But nobody is coming forward to do that. Why?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Mr. Viren Shah is there. He can answer.

SHRI VIREN J. SHAH. Do you want me to answer that?

SHRI E. BALANANDAN: No. No. Before I complete . . . (*Interruptions*).

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): In West Bengal, your own Government wanted that power should be in the private sector.

SHRI E. BALANANDAN: For the time being, I am not concerned with any Government or any personality. I am only referring to a general argument about privatisation of power sector. I tell you, friends, power sector is a sector where private employers seldom come in because power will not immediately bring profits for them. Private employers are wiser than you and me. In India we have produced 64,000 megawatts of power. We have energised nearly 400 lakhs of villages. If power is given to the private sector, will they go to villages? No. Not, only that. If a project is taken up, it will take five years to complete it. We know that a megawatt of energy generation requires Rs. 3 crores And you have to wait for five years for getting returns. Nobody is willing to come forward to do that. That is why despite the requests of many big people nobody from the private sector is coming forward. Let the private sector come in and do business. I am not against that. Workers are not concerned with public or private sector. Without workers

[Shri E. Balanandan]

nobody can produce anything. We are not very much concerned with public or private sector. We are concerned with the development of the country. If you want to develop power, it should be in the public sector. Otherwise nobody will come forward to invest money and develop power sector. That is the point we are concerned with.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Please be brief There is paucity of time.

SHRI E. BALANANDAN: Now let me come to the situation in Delhi. We, the so-called VIPs, stay in Delhi. In the statement it is stated that steps are being taken to strengthen the load which we require. The other important. There are two main bottlenecks. One is that the transmission line is weak. That line cannot carry the lood which we require. The other is, we are not having sub-stations which can carry power to Delhi. The distribution centres, the power stations, are overloaded. The transmission line is also overloaded. They trip and Delhi goes dark. The Government is saying that it is going to take steps. Those steps should be taken with a time-frame, within a particular span of time. Two things have to be done for Delhi. One is, the whole transmission line which is weak should be changed. The other is, the sub-stations which are weak, which cannot carry load, should be strengthened. If these two steps are taken, Delhi's power problem can be temporarily solved. For solving it, the Government should have a deadline, say one month. I have experienced in Kerala that within 62 days we have erected sub-stations in the State. So you can do it within 60 days in Delhi provided the Government gives funds. Likewise, you should have a time-limit for strengthening the transmission line too.

Sir, the following steps should be taken if at all the power sector problem should be handled effectively. First of all, we must declare that production of at least 38,000 megawatts of power will be taken up in the Eighth Power Plan. Also steps should be taken to reduce the transmission losses which are about 22 per cent to 30 per cent. This can easily be lowered if proper steps are taken. Improvement in the PLF should also be attempted by the Government seriously.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Now please conclude.

SHRI E. BALANANDAN: We must have a National Grid. You see, in some States, we are having surplus power. In some States, no potential of power is there. Therefore, the National Grid is a must. Even in our areas when the power goes off, if a National Grid is there, simply you can switch on and see that the power problem is temporarily eased.

Now I come to clearance of pending projects. There must be a time-frame—10 years, 15 years—for the clearance of pending projects. Project reports are sent to the Central Government for clearance but the same are kept there. Scientifically prepared reports or the reports with which the experts agree, they remain pending. Somebody in the Centre wants to delay the projects; some environmentalist, who does not know the subject properly, comes in the way of its implementation. They do not know much. Therefore, I am saying that there must be a time limit for clearance of projects.

In coal supply, two things are there. Coal is not supplied in time to the projects and coal cannot be produced because there is no power. This is an anomaly. If you have a plan in the coal mine areas, if coal mines can prepare their own plan to supply electricity for the coal mining, then why should they wait for others? There have been coal at the pithead. They can have a

small project so that the supply can be maintained. Therefore, coal production need not be interrupted. The quality of coal is not being maintained. We are talking of plant load factor. It cannot be improved unless the quality of coal is improved. So the quality of coal has to be improved.

Another factor we are talking of is about Electricity Boards. They are always in the red and somebody was saying here that the coal managements have to get thousands of crores of rupees from the Electricity Boards and Electricity Boards have to get thousands of crores rupees from the State Governments and Public Sector Companies. How can the Electricity Boards function? Both are under the Government. One is complaining against the other. The Central Government has no policy on this question. The Electricity Supply Act needs drastic change. There are very many experts in this field. The engineers and the technicians, who are working in the Electricity Boards, are well-versed in the subject but the workers have no say in it. The engineers and the workers, who are working in the Electricity Boards, are not given proper representation as per the Electricity Supply Act. I request, through you, Sir, the Minister that the Electricity Supply Act should be amended so that the engineers and the workers, working in the Electricity Boards, can have proper representation in the Board.

Then the problem of theft is there. I cannot say who is responsible for that. Somebody was saying that the employers are doing it mainly because they can easily bribe the Board's workers or somebody who is there. Sometimes, the engineers also do this business. But theft can be easily located if the Electricity Boards or the supplying agencies are serious about it. In that case, this can be easily located and the culprit can be brought to book. But I do not know how to handle it. Those people who handle it should be serious about that.

And finally about the gas projects. Gas is a wealth now newly coming to us. This can be utilised for immediate short-term production of current which is possible within one year or one and a half years. If we have gas available, we can start electricity generation, but to our bad luck, the Central Government, are not having a vision how to utilise the surplus gas we are having. We were requesting from the South, Kerala and Karnataka, that a pipeline should be laid from Bombay to Kerala so that we can have electricity generation in those areas also. Gurudasji told us that gas line was not going there. So this gas line should be extended to the east as well as to the southernmost corners so that this can be utilised for generation of electricity.

SHRI CHATURANAN MISHRA (Bihar): Bihar and Bengal also.

SHRI E. BALANANDAN: Bihar and Bengal I have mentioned already. This pipeline should be extended to Bihar and Bengal also.

Finally, I say that a national grid is a must. By having this national grid every State in the country can be supplied with energy. Before I close, I request that a full-fledged discussion in the House should be arranged so that the House will be able to take up this serious question of power shortage. This crisis of power is a crisis which is inbuilt in the plan itself. Therefore, the plan should be changed and the original plan of 48,000 MW for the Eighth Plan period and 66,000 MW for the Ninth Plan period is a must; unless we attain this target, our problem cannot be solved.

[The Vice-Chairman (Shri Bhaskar Annaji Masodkar) in the Chair].

SHRI VIREN J. SHAH: Mr. Vice-Chairman, to begin with, what my friend comrade Gurudas Das Gupta

[Shri Viren J. Shah]

mentioned about the hon. Minister, Shri Kalp Nath Rai and his *kalpana*, giving credit for his statement, all of us have had the experience that the statements are hardly written by the Ministers, hardly ever. I would be very glad if this hon. Minister did its. And the tributes Shri Gurudas paid him about his *kalpana*, his imagination, is befitting. But if you go back to the statements made in this very House or the other House 10 years back or 20 years back, except changing the numbers, it would read exactly like this. Achievements, efforts being made, good intentions and the result we know what it is. I would just switch to what comrade Balanandan said when I came in and from the Chair I was directed that Shri Shah would reply to privatisation etc. I am not bothered about privatisation or public sectorisation but the only thing I am worried about is that the resources employed should give results and returns to the country and I am very happy when hon. Mr. Balanandan told us that Kerala Electricity Board's performance is better than that of Tata Power Supply Company. If it is so, it is something very great because I have a lot of data about the Tata Power Supply Company, Rihand Power Plant, Bihar and others. But if Kerala is doing like this, then there is a lesson for other State electricity boards to learn. If Kerala can do that, why not others? While I slightly disagree with others by saying that it would not be proper for us to keep blaming the officials or the technicians or the technocrats in State electricity boards, the fault lies with the politicians who control these electricity boards, who make them non-functional, who make it difficult for them to take any efficiency measures in many ways. And we we have heard Mr. Ahluwalia who always comes extremely well-versed with diverse subjects, from family planning to power generation. I respect him for that. On the generation of power how poor we are: On distribution losses this is not something new.

3.00 P.M.

This has been debated many times. Mr. Kalp Nath Rai was Minister of Power earlier and even much before that as a Member of Parliament he had seen and must have spoken about it, and I am speaking just now. There is somewhere a very serious lacuna in our ability to make people or enable people to perform. About Rs. 2,000/- crores the State Electricity Boards are not paying to the Department of Coal and Mines, not paying to the BHEL and the BHEL, in turn, not paying to their suppliers. The very disturbing situation of the whole economy is due to a number of things. I am not going into public sector and private sector because I have a disadvantage that in the last three, four or five years. I have made reasonable study of the economics of China, Soviet Union, Poland, Hungary; Czechoslovakia. And what is Mr. Gorbachov asking right now to G-7 just now sitting in London? The Parliament should speak about it because it was very useful for us to learn from Lenin and Stalin at a particular time. But today we do not want it. What do we have to learn from the Soviet Union or anyone? So I am not going to talk about it. No need for Mr. Dipen Ghosh to interrupt. I need not talk about it. But what I want to speak about is: Are we really serious and sincere—all of us, in particular the treasury Benches —in making a reasonable change? Now, so far as the State Electricity Boards are concerned the stock answer from anyone sitting there would be that they are with the State Governments and Centre has only a limited power, etc. But, interact with them to find out ways to reduce the 22 per cent loss on an average. The loss in individual States is more. If you take the State from which hon'ble Ahluwalia has the great privilege of coming, and I respect that great State from where Buddha, Mahavira, Ashoka, Samart Chandragupta Maurya

and Mr. S. S. Ahluwalia come, it is making a loss of 40 per cent and it is going on. It has nothing to do with Mr. Lalo0 Prasad Yadav or any other Yadav. I have great respect for all of them. This is something going on. Here I would like to mention what I heard from a learned person that in the United States there are one thousand rural co-operative power generating systems. Because power was not going to the rural areas and because the power companies could not afford it, the rural co-operative power generating systems started and there are one thousand such co-operative societies generating power meeting the needs of the rural area—generating and supplying, I repeat. This is what I heard. Now, we have a rural electrification scheme. I also heard from another learned economist sitting there who told me that we have a rural electrification scheme but our results have not been what they should be. Now my submission would be that it is a practice to provide for additional power generation in every plan. I remember that when Mr. George Fernandes was the Industry Minister in 1977, in that plan 25000 megawatt additional power was to be produced. I think, 14 years have passed since then. They might have produced. Now, we come with 38000 mega watts of new capacity to be created. Would the hon'ble Minister take pains, first of all, to see that the capacity which is there where the people's money the country's wealth is invested, how do we pull it up by the ears? What do we do from the Centre and from the States to enable that the money invested by the poor people-whom Mr. Manmohan Singh is going to tax on the 24th of this month and we have been taxing them all these years regardless of whichever Government is in power—gives results? How are we going to ensure that this investment gives results to the people? What I saw in my election campaign in the rural areas towards the end of January was, there was crop standing there. There was water in the well and the farmers were having tears of blood in their eyes and they said, "the water is there; the crop needs water, but there is no power to draw it with our pumpsets and the motors fitted there."

"Do something. My wheat crop is going to wither away." This is happening all over India. This is where perhaps the honourable Minister might want to look at. Don't bother that the private sector has not done it. For ten years Minister have been talking about it. Mr. Vasant Sathe the great wanted to do but could not bring about anything, because there is an animal here in the Government called the Committee of Secretaries. That animal is a 12-legged animal with four different heads, six different tongues. And it connot come to any conclusion except to find only the least common factor, to say "no". Whether the Energy Minister comes up or whether the Energy Secretary comes up with a sensible scheme, it would be shut down. That is why I have a specific suggestion. You have the World Bank reports. The World Bank must be condemned except for going to them for taking money from them—12 billion dollars on which we keep paying interest. But I still condemned it because of my socialist angle—socialist, I put it in quotes. And I say naturally both the socialist countries, the biggest countries, are now wanting to be members of the IMF and are wanting to get money. But the data given is that the overloading of transmission and the distribution systems in Indio are such that though we make investments in additional capacities, we do not make adequate, commensurate, investment in the transmission system. And then you start with the low voltage transmission. Then we have the thermal projects, the mega projects, super themal power stations, and so on. But again the transmission|distribution facilities are not commensurate. So, look at that first. Here is the UNCTAD report of 1989. "We have a highly dispersed distribution system

[Shri Viren J. Shah]

like the industrialised world. Though Korea, Thailand, Molaysia, etc. have a similar system, they have the high system reliability but we don't have that high system reliability. That is why what happened in Bengal, in Bihar, in eastern India, was due to the non-maintenance of stations, non-maintenance of power plants, non-replacement of minor things; for eight months, ten months a small thing would not be replaced; budget constraints and what not. And a whole three, four, five States get into total darkness at noon. So work up even on the dispersed distribution system. How is that the smaller countries are able to do a thing which we cannot? And we claim ourselves to be much more intelligent and capable than all of them! How are they managing? About the transmission losses I am not going to speak much because while the average transmission loss in other countries is 10 per cent, here the average is 30 per cent, 40 per cent, in a particular State...

SHRI KALP NATH RAI: 49 per cent in Jammu and Kashmir.

SHRI VIREN J. SHAH: One must be ashamed of it. If I were the Minister of Power, I would commit suicide right now...

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE (Maharashtra): I object to it. We don't want this House to close down.

SHRI VIREN J. SHAH: I said it metaporically.

SHRI S. S. AHLUWALIA: The Member is provoking the Minister to commit suicide. It is a serious offence to commit suicide.

SHRI VIREN J. SHAH: Outside the House it is an offence. I would consider myself a great speaker if I can provoke Shri Kalp Nath Rai to take such an extreme step which may be a great loss...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Talk on power.

SHRI VIREN J. SHAH: Coming back to my point, if there is such a high loss of 49 per cent and if we don't take note of it and if we allow it to happen, six months later again there will be another Calling-Attention or another debate. We don't want to turn the Parliament into a talk shop...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): It is always like that.

SHRI VIREN J. SHAH: We want it to be an action shop...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You are giving the smile of a shop. That is being objected to.

SHRI VIREN J. SHAH: Talk shop is not objected to. My inspiring him to commit suicide as a metaphor is objected to.

Then there is the problem of lower voltage supply. This is the complaint in the entire country. It happens in Delhi and other places. This is where your maintenance comes. When your voltage is reduced, it causes a loss to equipment, it causes a damage to our equipment. Whether it is in the public sector or in the private sector, something should be done to prevent this is low voltage supply. Indian thermal power plants have a low thermal efficiency plant availability and plant load factor *vis-a-vis* Korea, Malayasia, and Thailand and other countries. I would like to come to a couple of things. This morning we talked about flaring of 14 million cubic metres of gas per day. The Maharashtra Government have taken a serious note of it. I would request the hon. Minister to pay attention to this. Fourteen million cubic metres of gas is being flared in the western off shore region. The Maharashtra Government has represented several times that a second gas terminal be set up at Uran to produce power. The ecology is taken care of and the environment is also not affected. At the

same time, cheaper power is made available for use. Fourteen million cubic metres of gas is being flared every day which is a criminal waste to the nation. If this waste could be arrested, we could reduce taxes, we could reduce the cost of kerosene to the poorest person who does not have electricity at home. Instead of that we are just flaring it away. The Maharashtra Government has suggested that they could have a second gas-based generation station. Will the hon. Minister consider it. This proposal has been lying with the Government for quite some time regardless of whichever Government has been in power. We could think of using this flared gas to meet the increasing demand-supply gap in all major Indian cities. Energy conservation measures have been very significant abroad. We are talking of energy conservation in India. Government has talked about it, consultants talk about it, private sector talks about it and yet there is tremendous scope for achieving that in India. I have got data here from the International Energy Agency which says that several member-countries have decreased energy consumption per unit of GDP by twenty per cent from 1973 to 1985. If that happens in our country we could have a total sea-change in the economic scenario. An investment for 38,000 MW of power is recommended. I am not against that. But, what I am saying is, before I invest one rupee more I would like to know what I have done with the rupee I invested yesterday. When you do take investment decisions I want you to consider this aspect. The Government is a whole thing and there are several ministries and there are inter-ministerial constraints. One of the hon. Members mentioned in the morning about environmental angle being taken up. That is very important. Environment is very important for human beings to survive. But, it has to be blended with reality. We cannot have the Environment Ministry sitting over a proposal for 6 to 12 months and increase the cost by 10 to 15 per cent. Secondly, when you do decide, release the funds immediately.

I remember in this very House many years back I heard about generation of power through ocean waves. Again last year or a year before, Dr. Naunihal Singh—he was a Member of one of the Houses—also made a mention about the generation of ocean-based energy and a particular mention was made about Kutch coast that this could be done, and I keep on hearing off and on that this experiment is being thought of, it is being done, they are trying something etc. But, like everything in the Government nothing moves straight. Everything moves in a circle. Even a snail moves in a direction. Here, we go round in a circle and six years later also you will get the same answer about generating ocean-based energy because somebody in some department will give one reason as to why it should not be tried instead of saying how it could be done. Will the honourable Minister leave his imprint and leave his mark on this Ministry by doing one of these things at least, that is, generation of energy from sea waves and a number of other steps which I have suggested by which they can improve the performance of the State Electricity Boards they can prevent the sudden closing down of equipment due to low-voltage power being supplied, and they can improve generation, transmission and distribution of power and stop-they cannot stop; at least they can reduce—the theft of power and energy? The Minister must set a time-limit and he must be able to say that within twelve months he is going to achieve this. There is one thing great here. I am very happy about one thing because in their election manifesto they have time-bound programmes for a number of things. This is the first time that there is a time-bound programme for everything. Otherwise it is all declaration of intentions only Look at the replies given by the Government this morning: "It is being considered", "It is being look-

[Shri Viren J. Shah]

ed into" and so on. There I think that the honourable Minister can move in the direction of their election manifesto and take upon himself the responsibility and must be able to tell this House, "I will see that this thing will be done within thirty days." Achievement may take time, may take three months or six months. But that does not matter. He must be able to tell the House, "In thirty days I will do it, in four weeks or in eight weeks or in twelve weeks I will do it", so that we can hold him responsible and ask questions right on the floor of the House after the said period. If you move in this manner, your machinery will also move in the same way. I am saying this because I do not believe in blaming the bureaucracy or the concerned people. They will work as per the clear-cut directions given to them and if they know that the intentions are sincere and honest and well-meaning. But clear-cut direction must be there and a time-bound programme must be there. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Ram Awadhesh Singh. Not here. Yes, Mr. Bhandare.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Sir, I am really impressed by the very incisive, very much in-depth, well-prepared and well-delivered debate that we have been witnessing all this time on very very important question of shortage of power supply in our country.

Sir many Members have said many things about the deficiencies, about the transmission losses, etc. But one thing which at the cost of digressing a little, I would say is that we must also do a little introspection and tell ourselves that we should also be extremely careful about the time losses in this House!

Sir, I think the time has come now to improve our work culture, all around. Today, the difficulty is that in every walk of life—I do not want to pick up any one section--there is no commitment to excellence and there is so dedication to work and I think that this commitment and dedication will come only when the people at the top show them the why to do it. So, more and more informed debates, more and more objective debates, should be there which will push the country forward—debates not on small debating points, but on matters of substance, on matters of progress. This is by the way, and now I come to my main points.

It cannot be denied that the future of mankind will be governed by two basic things: communications and energy. If we have greater energy, if we have a very efficient network of communications, we can move towards prosperity. And, when you move towards prosperity, you will find that there is no greater contraceptic than prosperity, and here I think the Hon'ble Member Dr. Reddy will agree with me.

SHRI VIREN J. SHAH: Hundred per cent.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Therefore we must think of the future which is bright, the future which will contain the population and bring about a greater measure of fulfilment and dignity to the lives of the millions today in our country, who are down-trodden, who continue to starve, who continue to be without work and who lead almost a life of animal existence. Fortunately, we have a Power Minister who physically shows what power means. (*Interruptions*) His interventions in this House are too well known Anything he does he does it very powerfully, and I have very high hopes in him. He has started well and I do expect him to put in all his power to achieve the power objective of the Government.

Many statistics have been quoted. I do not want to go into that agoni. The Eighth Five Year Plan expert group suggested a capacity of 48,000 MW. The Planning Commission has pruning and cutting scissors which are ever readily available and the Ministry of Finance has better and sharper scissors. They cut it down to 39,000 MW. This downward trend in energy

growth in the long run is going to be counter-productive. It will increase the cost of power, it will affect agriculture, it will affect domestic supply and it will cause untold misery to the people of this country. Please use your power to see that this imbalance is removed. I want to take you to more important and practical aspects. One is the acute shortage during what is called the peaking hours. The supply always has peak hours. It has also lean hours. During night it has lean hours. And during the evening time, you will find, it is peak hours. Now, there is no method I have seen whereby you increase the supply during the peaking hours and cover the peaking shortages and there is no way—I mean, at least the thermal power is not that efficient to reduce when the demand is less on the power supply. It is here that I join wholeheartedly with what my friend, Mr. Viren J. Shah, has said. It is not Bombay bias or it is not Maharashtra bias at all, because I started my career in Parliament by being a member of the Consultative Committee of Petroleum Ministry. I still remember when I said that the production of 10 million tonnes of crude would in a matter of five years go up to 30 million tonnes everybody laughed at it. But it proved to be true. Now the Hon'ble member has given the figures. These figures are too well known as to what is the gas which is flared and all that. But the only solution to the problem to provide cheap energy is to provide greater gas-based power stations Now there are constraints which the Minister must be knowing of the hydel power and of the thermal power. But these constraints are not there so far as gas-based power is concerned. Two things must be understood. Apart from being cheaper, the gas-based power stations can be located all around. It is a matter of common knowledge that the period it takes to construct one gas-based power station is roughly about three years. I know that there is some imbalance created in this situation by the Gulf War. In fact in the Eighth Five-Year Plan, there is about 7,485 MW capacity envisaged from the gas-based power projects. I have not worked out but there may be a little impact of the Gulf war, there may be a little scarcity of gas turbines. But as I understand, it is going to be short-lived. I am not sure because I am not an expert on this. But let me make it clear that we have to throw the idea, and the Government has to execute it. May I request the hon. Minister to answer this first question as to how does he plan to cover up the peaking shortages and to what extent does he go in for these gas-based power projects?

Then, Sir, I come to a more specific thing, and I speak of the South. I find for the last two days everybody is talking about Cauvery and water, but nobody is talking about the shortage of power. Is it realised that the Southern States have been totally discriminated in the matter of having power? And I shall be happy if the hon. Minister corrects me. Look at what is happening. I think, in every session, there are four or five questions about the Neyveli Lignite power station. Five years have gone and nothing has happened. How can you admit of such a situation? I would like some sort of an assurance from the hon. Minister that he will see that the Neyveli Lignite project takes off within a period of one year from today.

Sir, now I come to a few things about the Capital. I raised it the other day; you must have seen it. The hon. Minister has started with a great gusto. He has set up an electronic complaint and monitoring cell. Let me tell you. You have inaugurated it but it does not work. I have given the day; I think it was last Thursday when electricity was completely cut off for 12 hours at my home. I could not get the DESU Manager. Mr. Pradhan was not available at his house. Nobody could give any responsible reply. You

[Shri Murlidhar Chandrakant Bhandari]

have stated that there are 21 lines. But I could not get even the complaint cell. And when I got there with great difficulty, the same was the position. The Sub-station from where the supply is given was shut. Now, we all realise that the Government is working under extreme constraints. And we as citizens do not want merely to criticise the staff or anybody. We want to cooperate with them. We want to help them, whether it be police or DESU or Municipal employees or Government employees. But it does appear that the Government employees and the Municipal employees do not want to take our help. The whole sub-station was abandoned. There is a total communication gap, a failure of public relations between the consumer on the one side and the Authorities on the other. There are two suggestions I will make. Sir, you have an open house meeting with the different consumers which come under your scope of activity and try to look into their complaints. The second thing is, whenever there is a power shortage and when we go to the sub-station to find out what is wrong and where the fault is have a blackboard, where you will clearly indicate that this is the reason today and that we are not getting supply from this place or that place or there is a collapse of grid. Whatever reason is there that should be given. And like the airports where you show estimated time of arrival when it is late or estimated time of departure, the estimated time of resumption of power supply should also be given. People will at least read the board and go back. Here people are waiting because there is nobody to answer. And sometimes it becomes a law and order problem also. I must tell you I am not prepared to give you a clean chit because today DESU is full of inefficient and corrupt staff. Their motto is not "connect and collect". It is amazing. For the shortage there is no excuse at all. The first thing that the DESU does is to disconnect the vital supply to anybody. I think their motto should be "connect and collect". And once they disconnect what happens is that nobody really knows except DESU because that poor consumer is compelled to live on the theft of electric energy by greazing their palm. I read somewhere that action has been taken against 6000 persons. This is a matter of attitude. This is a matter of administrative reforms. Today the policy is that to the extent it is possible you give electricity. I can tell you, in 1970 even in unauthorised colonies in Bombay we made it a prestige issue and it was included in the first manifesto of 1971 elections that unauthorised or authorised, no human being will be deprived of the basic necessities like water, electricity supply, air and other things. I think you should also follow these policies to which the Congress at all times stands committed. These are some of the points which I have mentioned. I do hope that we will today realise and work together as Rajivji used to say, so that we make our country a modern country full of technological advances and self-sufficiency, so that no longer do we have to go with a begging bowl to any other country.

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, सदन ने बहुत समय इस पर लिया है और इस पर गम्भीरता से विचार किया है। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बातें मंत्री महोदय तक पहुंचाना चाहता हूं जिससे उनकी याददाश्त में यह सारी बातें रहें और सचमुच में जो बातें कही जायें उन में से कुछ काम वे कर के दिखलायें जिससे राष्ट्र भी आगे बढ़े और प्रांत भी आगे बढ़े। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विद्युत हमारी आज सब से बड़ी जरूरत है। हवा और पानी के साथ रौशनी भी जरूरी है और इस सरकार को सब से पहले इस बात के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा कि आप देश को अन्धकार में रखना चाहते हैं या प्रकाश की ओर ले जाना चाहते हैं। सब से पहले आप को ऊर्जा की स्थिति ठीक करनी होगी।

इसलिए मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं।

आपने जो सवेरे अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया उसी से 2-3 बातें पहले मैं जानना चाहता हूं। स्वयं आपने यह स्वीकार किया है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में मुख्य तौर से ऊर्जा की 10 प्रतिशत कमी है। मैं जानना चाहता हूं कि इस 10 प्रतिशत कमी को आप कब पूरा करेंगे और इसके लिए आपने कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया है।

दूसरा, जब केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की संरचना की गई थी तब आपने स्वयं यह कहा था कि इसका उद्देश्य यह था कि ऊर्जा जैसी जो बहुत ही आवश्यक चीज है उसको केन्द्र अपने हाथ में लेगा। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि केन्द्र का वह प्रस्ताव, जो 1984 में कांग्रेस ने अपने चुनाव के मैनीफैस्टो में लिखा था और 1984 में ही कहा था कि यह सरकार इस तरह से विद्युत के लिए नीति निर्धारित करेगी कि केन्द्र के हाथ में विद्युत हो और जिन प्रांतों में विद्युत की, ऊर्जा की कमी होगी उस प्रांत को सेंट्रलाइज्ड रूप से हम देंगे, इसके बारे में दूसरे लोगों ने भी आपका ध्यान आकर्षित किया है, मैं जानना चाहूंगा कि इस संबंध में सरकार क्या सोचती है? और अब भी उसकी यह नीति है या नहीं?

तीसरा, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें सरप्लस पावर हो रही है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें ऊर्जा की कमी है। तो क्या आपकी कोई ऐसी नीति है कि अगर पड़ौसी राज्य में सरप्लस जनरेट हो रही है और उसके बगल के राज्य में बिल्कुल अंधेरा है तो वहां से लेकर उसको देंगे, या सीधे दिल्ली को भेज देंगे। यह इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी एक हफ्ता पहले माननीय मंत्री महोदय ने रिहन्द में एक उद्घाटन किया और वहां से बिजली सीधे दिल्ली को भेज दी। लेकिन वहां से बगल के प्रांत उत्तर प्रदेश और हमारे प्रांत बिहार में न तो कृषि के लिए बिजली है न उद्योगों के लिए है। एक ओर जहां कृषि में ऊर्जा के लिए लोग तरस रहे हैं तो दूसरी ओर उद्योग के लिए भी तरस रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप पहले उनको देंगे या सीधे दिल्ली में रोशनी पैदा करेंगे?

अब मैं मंत्री महोदय का ध्यान सीधे अपने प्रांत की ओर ले जाना चाहूंगा क्योंकि पहले मैं अपने घर में दिया जला लूं फिर उसके बाद दूसरे की चिंता करूं। आप जानते हैं कि बिहार राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवां है लेकिन आबादी की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान रखता है और वहां की जो बिजली की पोजिशन है मान्यवर उस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे इस राज्य में प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश मात्र 242 रुपये है और पंजाब में 1150 रुपये उसी तरह से इस राज्य में बिजली की स्थिति यह है कि जहां पूरे भारत में प्रति व्यक्ति 65.15 वाट्स बिजली उपब्ध है वहां बिहार में सन् 1988 तक जो स्थिति थी उसके अनुसार 45 वाट से भी नीचे बिजली प्रति व्यक्ति लोगों को उपब्ध थी। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत सरकार के पास बिहार की 7-8 ऐसी योजनायें लम्बित पड़ी हुई हैं जिन पर भारत सरकार ने कभी भी गम्भीरता से विचार नहीं किया और इसके लिए मैं मंत्री महोदय को बहुत दूर नहीं ले जाकर आज के अखबार "हिंदु स्तान टाइम्स" में जो खबर आई है, जो बहुत प्रमुख है, उसकी ओर ले जाना चाहता हूं। उसमें है:

Bihar Power Projects await clearance

यह समाचार मैं आज के अखबार से ले रहा हूं, पुराना नहीं ले रहा हूं। कोयलकारी योजना आपके यहां विचारार्थ पड़ी हुई है। चांडिल जमशेदपुर की योजना है जिसमें 500 मेगावाटस दो यूनिट्स में पैदा होंगे। यह जरूरी योजना आपके सामने लम्बित है। दूसरा टेनूघाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट की 210 मेगावाट की तीन यूनिट्स की योजना है जिसमें मात्र आपको 825 करोड़ रुपयों का खर्च करना है। तीसरा, कदवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 75 मेगावाट का आपके यहां है जिस पर आपका 337.70 करोड़ रुपयों का खर्च होगा। और बिटा पावर प्लांट 67.5 मेगावाट का जो दो यूनिट हैं, जिसका खर्च 337 करोड़ रुपया होगा।

[श्री शंकर दयाल सिंह]

पांचवां मुज्जरपुर धर्मल पावर प्लांट है 250 मेघावाट का दो यूनिट का, वह भी आपके यहां विचारार्थ पड़ा हुआ है और सब से जरूरी दो ऐसी योजनायें आपके यहां विचारार्थ पड़ी हुई हैं, जिनकी ओर मुझे बहुत तरस आता है कि भारत सरकार ने अभी तक कुछ भी ध्यान नहीं दिया । एक तो कोयल कारो योजना, जिसके बारे में मंत्री महोदय ने जब वह मंत्री हुए, तब माननीय मंत्री महोदय, श्रीकल्पनाथ राय जी ने जो मंत्री के रूप में कल्पना भी रखते हैं और पावर मंत्री के रूप में पावरफुल भी समझे जाते हैं और सदस्य के रूप में भी पावरफुल थे, कोयला कारों के बारे में इन्होंने कहा था कि इसको मंजूरी दी जाएगी।। लेकिन इनके कहने के बावजूद भी मंजूरी नहीं दी जा रही है और न ही इस पर ध्यान दिया जा रहा है ।

और अंतिम दो योजनायें जो आपके यहां लंबित हैं, मान्यवर, 1988 में जब राजीव गांधी जी बिहार में गए थे, तो उन्होंने नवी नगर बारुण, औरंगाबाद में बहुत आवश्यक योजना है, वह आपके यहां लंबित है, जिसका सर्वे हो चुका है और जिसके बारे में वहां के तत्कालीन मुख्य मंत्री से लेकर प्रधान मंत्री तक, सबों ने घोषणा की थी कि इसको हम बनायेंगे, यह भी आपके वहां विचारार्थ पड़ी हुई है ।

हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर दें, तो केवल बिहार की आठ करोड जनता के बीच में ही बिजली नहीं जाएगी, बल्कि बिहार अतिरिक्त बिजली की सप्लाई दूसरी जगहों में भी करेगा । मान्यवर, यह कहने की आवश्यकता नहीं है, मगर कहना बहुत जरूरी भी समझता हूं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, और बंगाल—इन तीनों जगहों में बिजली का भयंकर संकट है और यह संकट देखने में अभी-अभी हाल में आपको स्मरण होगा कि 1990 में एक दिन ऐसा आया कि बिहार और बंगाल में न तो कोई उद्योग-धंधा चला, न तो कहीं रोशनी दिखाई दी। मैं समझता हूं कि यह जून 1990 में हुआ था और जो ओर दो जुलाई, को, मैं हाल की ही बात कर रहा हूं, बिहार और बंगाल दोनो जगहों में इतना बड़ा संकट बिजली का पैदा हुआ कि दोनों जगहों में उद्योग-धंध भी बंद रहे। यहां तक की जो गाड़िया बिजली से चलती है , वह भी समय पर नहीं पहुंची राजधानी एक्सप्रेस जैसी गाडी भी बारह-बारह, चौदह-चौदह घंटे उसके कारण लेट पहुंची ।

इसलिए मैं आपसे बहुत अदब के साथ दो-चार बातें करना चाहता हूं, जिसे आप अपने आखिरी बयान में क्लियर करेंगे, यह आशा रखता हूं । एक तो यह है कि आपका इस संबंध में लक्ष्य क्या है । आप अपने लक्ष्य को बिलकुल निर्धारित करते हुए, समयबद्ध बता दें कि समयबद्ध तरीके आप इसकी पूर्ति कब करेंगे ?

दूसरी बात यह बतायें कि बराबर इस तरह की देश में बहस चलती रहती है कि बिजली के उत्पादन को निजी क्षेत्र में ले जाएं, कि सरकारी उपक्रम में हम रखें । यह सार्वजनिक क्षेत्र मे ही रहेगा कि यह निजी क्षेत्र में जाएगा।मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं पर कई ऐसे औद्योगिक घराने हैं, जो कहते हैं कि आप हमको दे दीजिए, हम चला लेंगे और कई जगहों में—बम्बई और कलकत्ता जैसे जगहों में यह चलायें चलती हैं कि सार्वजनिक रूप से हम इसे सार्वजनिक उद्योग में नहीं चला सकते हैं, तो हम इनको निजी फर्मों को सौंप देंगे । इसके बारे में भारत सरकार की और आपकी नीति क्या है ?

इसके साथ ही एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूं । मैंने प्रारंभ में ही कहा है कि मैं बहुत फालतू बातों को नहीं कहूंगा, पर खास मुद्दों की ओर आपका ध्यान इसलिए दिला रहा हूं, जिससे कि आप उनके बारे में कुछ कर सकें और उसमें आप हमें राहत दे सकेंगे । वह यह है कि एक नीति आप तय करें कृषि और उद्योग के संबंध में , कहीं न कहीं उसकी सीमा का निर्धारण होना चाहिए – किसी क्षेत्र में अगर कोई औद्योगिक क्षेत्र है और पास में ही कोई कृषि के लिए सब से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, आपको उसके लिए बांटना पड़ेगा कि आप कृषि के लिए जितनी बिजली मुहैया कर रहे हैं और उद्योग के लिए कितनी बिजली मुहैया कर रहे हैं ।

मैं अपने प्रति से कम से कम इस बात को जानता हूं कि न तो बिहार में कृषि के लिए बिजली मुहैया है और न ही उद्योग के लिए मुहैया है और खेती भी समाप्त हो रही है, और दूसरी ओर हमारे उद्योग-धंधे भी समाप्त हो रहे हैं। तो इसके लिए एक सीलिंग बनाना सबसे जरूरी है। सब से जो जरूरी बात है उपसभाध्यक्ष जी, जिसकी ओर आज सवेरे इस सदन में पहला प्रश्न जो हुआ था वह कोयले के इंपोर्ट को ले करके सब से दुखद स्थिति यह है कि कोयला का संबंध बिजली से है और बिजली का संबंध कोयला से है। जो हमारे थर्मल पावर स्टेशन हैं वे कहते हैं कि हमको बढ़िया कोयला की उपलब्धि नहीं होती, कोयला क्षेत्र कहते हैं कि हमको बिजली की उपलब्धि नहीं होती है इसलिए हम उत्पादन ठीक से नहीं कर पाते हैं। इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। कोयला और बिजली इन दोनों का जब तक सामंजस्य स्थापित नहीं करेंगे, और इसके लिए जरूरी है, कि जहां कोयला खान हैं वहां थर्मल पावर स्टेशन भी रहना चाहिए जिससे आपकी ढुलाई बचे और उन कोयला खानों को अधिक से अधिक विद्युत आप मुहैया कर सकें। यह भी आपको करना पड़ेगा जैसा कि आपको मैंने बताया, बिहार में मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं जिस तरह से कावेरी जल समस्या को ले करके बार-बार इस सदन में विवाद हो जाता है, लेकिन माननीय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान अदब के साथ दिलाना चाहूंगा, यह आप जानते हैं कि डी.वी.सी. का जब निर्माण हुआ था और आजादी के बाद सब से सफल और सब से पहले दामोदर वैली कार्पोरेशन का उद्घाटन करते हुए जवाहरलाल जी ने सब से पहले यह संज्ञा दी थी कि यह आजाद हिन्दुस्तान के नए तीर्थ-स्थल हैं। उस समय आप देखेंगे, आप पूरे ड्राइंग को मंगा कर देख लीजिए दामोदर वैली कार्पोरेशन का कि इसका सबसे ज्यादा विस्तार क्षेत्र बिहार में है। इसके 6 जो थर्मल पावर सेंटर्स हैं उनमें चार या पांच बिहार में हैं, लेकिन उसमें सब से कम बिजली बिहार को मिलती है, बहुत ज्यादा बिजली बंगाल को मिलती है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसको आप विवाद का एक मुद्दा बनाएं, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जहां अधिक जरूरत हो वहां आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। यह आवश्यक है। किसी प्रांत की बात नहीं लेकर पूरे राष्ट्र की बात को मैं चाहता हूं कि रखें।

माननीय, अन्त में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं 1971 में सोवियत संघ में जब गया, तो मैंने वहां के भारतीय दूतावास के एक सबसे जो पुराने पदाधिकारी थे मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा। मैंने पूछा कि इस देश में आप कब से हैं? उन्होंने कहा कि मैं 16 वर्षों से हूं। मैंने कहा कि 16 वर्षों में जो सब से उल्लखनीय चीज आपने देखी वह क्या थी? उन्होंने कहा कि 16 वर्षों में सब से उल्लेखनीय चीज मैंने यही देखी कि एक सैकेण्ड के लिए यहां बिजली कभी भी फेल नहीं हुई, बिजली गुम नहीं हुई। जब आप देखें कि ऐसे देश जो कि सब से अधिक ऊर्जा के ऊपर, बिजली के ऊपर ध्यान देते है यह देश विकसित होते चले गए। चाहे कोई भी देश हो। हम अभी भी विकासशील हैं या अविकिसत बने हुए हैं क्यों? इसलिए कि हमने असली समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया। भाई कल्पनाथ राय जी मंत्री के साथ-साथ मेरे मित्र भी रहे हैं। साथ-साथ हम लोग पढ़े हैं और उस जमाने में भी यह जो भाषण देते थे उससे लोग प्रेरणा ग्रहण करते थे। मैं समझता हूं कि आज माननीय मंत्री महोदय इस सदन में जो भाषण देंगे केवल भाषण के लिए नहीं, छपने के लिए नहीं, टी०वी० और आकाशवाणी के लिए नहीं, मेज थपथपाने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र की तस्वीर को सामने रख कर देंगे जिससे यह देश अंधेरे में नहीं डूबे बल्कि उजाले की ओर चले। धन्यवाद।

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं कृतज्ञ हूं आपका कि ऊर्जा की, कमी के संदर्भ में जो ध्यानाकर्षण ... (व्यवधान)

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार): इसके बाद मेरा है।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : तुम तो बोलने नहीं देते हो, डिस्टर्ब करते हो राम अवधेश जी . . . (व्यवधान)

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, पावर की शार्टेज से देश चिंतित हैं और उस चिंता का इजहार मेरे मित्र श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया और अन्य साथियों ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से किया हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। वास्तव में पावर शार्टेज इस चुनाव के बाद जिस तरह से आयी है, वैसी कभी भारत के इतिहास में दिखायी नहीं पड़ती है। एक सरकार कांग्रेस के विरोध में आई थी और वह सरकार ऐसी थी जो कुछ लोगों के गद्दारी करने से आई थी। वह सरकार राजीव गांधी और कांग्रेस का चरित्र हनन करके सत्ता में आई थी। सिद्धांत-विहीन वह सरकार थी और कार्यक्रम विहीन वह सरकार थी। उसमें सो काल्ड प्रोग्रेसिव और रिएक्शनरी भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग समर्थन दे रहे थे। उसमें एक ऐसा अवसरवादी व्यक्ति प्रधान मंत्री बना था, विश्वनाथ प्रताप सिंह जोकि राजीव गांधी और कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपकर ऊर्जा ग्रहण करना चाहता था। भारतीय जनता पार्टी ऊर्जा ग्रहण करना चाहती थी और सबसे बढ़कर जो लेफ्ट फ्रंट था, वह ऊर्जा ग्रहण करना चाहता था। लेकिन हुआ क्या कि वह सरकार 11 महीने नहीं चली और विश्वनाथ प्रताप सिंह की ऊर्जा समाप्त हो गयी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ऐसा विश्वास हुआ कि ऊर्जा हमारे साथ आ जाएगी। वह ऊर्जा कितनी उनके साथ आई, यह इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को मालूम हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ कितनी ऊर्जा आई? गद्दार का जो हश्र होता है, धोखेबाज और विश्वासघाती का जो हश्र होता है, वह विश्वनाथ प्रताप सिंह की ऊर्जा से देखा जा सकता हैं। उसी में, जैसे त्यौहारों में ललई छट होता हैं, चन्द्रशेखर जी प्रधान मंत्री हुए और सत्ता को तोड़कर वह जिस तरह से ऊर्जा का स्रोत बने, वह सर्वविदित है। इसके अलावा सो काल्ड प्रोग्रेसिव कम्युनिस्ट लोग, वेस्ट बंगाल और केरल में ऊर्जा हासिल किए हुए थे। केरल की उनकी ऊर्जा चली गई। वेस्ट बंगाल की भी ऊर्जा चली जाएगी। अब कांग्रेस के पास ऊर्जा आयी है और इस देश की 85 करोड़ जनता ने विरोधी दल के लोगों को जो ऊर्जा दी थी, उस ऊर्जा का ह्रास स्खलन, गिरावट, अवसान, नाश—जिस रूप में इन लोगों ने किया हैं, उसे ऊपर उठाने में कांग्रेस को समय लगेगा और हम समझते हैं कि राजीव जी तो रहे नहीं, लेकिन उनकी धर्म-पत्नी सोनिया गांधी की प्रेरणा से नरसिंह राव, कल्पनाथ राय के मंत्री के रूप में, ऊर्जा की जो गति अवसान की ओर जा रही है, उसको ग्रहण करेगी। . . . (व्यवधान) . . .

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: What are we discussing?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Power situation.

DR. RATNAKAR PANDEY: Power is power. Listen, what is power and what is *oorja*.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Political power or electric power?

डा० रत्नाकर पाण्डेय : जरा सुनिए-

Listen what I am saying.

"विश्व के विद्युत कण, जो व्यस्त सकल
बिखरे हैं निरुपाय,
समन्वय उनका करे समस्त विजयिनी
मानवता बन जाय।"

मैं उस ऊर्जा की बात कर रहा हूं।

महोदय, अब मैं यथार्थ के धरातल पर आना चाहता हूं। देश में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्डस हैं, वे भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। अगर संयुक्त रूप से मंत्री महोदय ने उनका आकलन किया होगा, अनुमान लगाया होगा तो अरबों रुपयों का उनमें घोटाला है। उत्तर प्रदेश के बिजली बोर्ड में 300 करोड़ रुपए की कमी थी और मुलायम सिंह यादव,

विश्वनाथ प्रताप सिंह और चन्द्रशेखर जी की सरकार आने के बाद 15 महीने में 800 करोड़ रुपए का घाटा उस बिजली बोर्ड को हो रहा है। इन लोगों ने 15 महीनों में किस प्रकार से लुटायी की है इसका एक उदाहरण आपके सामने है। बिजली की दर बराबर बढ़ रही है, 14 पैसे, 15 पैसे यूनिट से आज कितनी ऊंची हो गई हैं और मैं समझता हूं कि आगे भी बढ़ेगी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, लेकिन इसका सारा बोझ जनता पर पड़ रहा है। महंगाई से इस देश की जनता की कमर टूट गई है क्योंकि क्रेडिटलेस, जिनकी कोई क्रेडिट नहीं होती थी ऐसे विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार सत्ता में आई थी। यहां छटवीं आर्थिक ताकत के रूप में हमने, हमारे राजीव जी ने भारत को दुनियां में खड़ा किया था, वहीं आज भिखारियों की कोटि में भारत आया है और ऐसा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया। यह कमर तोड़ मंहगाई जो आई, उसका बिजली के निर्माण में जो प्रयोग हुआ, मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि आप टैक्स तो बढ़ाते जा रहे हैं, बिजली की कंजम्पशन की दरें बढ़ाते जा रहे हैं और प्रोडक्शन में जो कुछ लगना चाहिए वह बिजली के कर से या बिजली जलाने वालों से आप वसूल कर रहे हैं, लेकिन योजनायें हमारी नीचे आती जा रही हैं, क्या इसकी समीक्षा आप करेंगे और अगर करेंगे तो वह समीक्षा क्या हैं ? यह सदन को बताइए।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल): पीठासीन हुए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं गांव का रहने वाला हूं और गांव के बारे में हर सरकार घोषणा करती है कि हम 18 घंटा बिजली दे रहे है, हम 20 घंटा बिजली दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तीन-चार घंटा भी बिजली वहां के लोगों को नहीं मिलती है। संसद के पटल और विधानसभाओं के पटल पर मंत्री, मुख्यमंत्री बिजली मंत्री ऐसे··· आश्वासन देते हैं। ···(व्यवधान)···

जो मंत्री लोग सत्य से परे आश्वासन देते हैं, वह आश्वासन बंद होने चाहिएं और यथार्थ आश्वासन उनके होने चाहिए। बड़े-बड़े पूंजीपतियों, कारखानेदारों, ब्लेक-मार्केटियरस और उत्पादन के नाम पर धधा करने वाले लोगों उधोगपतियों के जो बिजली के इंस्पेकटर होते हैं या उच्चाधिकारी होते हैं शहरों में, नगरों में वह किसानों की, कुटीर-उधोगों में उत्पादन करने वाले की बिजली काटकर इन सेठों को देते हैं और जो कोटि-कोटि जनता मतदान करके हमें सत्ता में लाती है, चाहे किसी दल को लाती हो, हम उनको अंधकार में रखते हैं, उनको ऊर्जाविहीन कर देते हैं। जिस देश की जनता ऊर्जा विहीन होगी तो सत्ता में चाहे किसी भी दल के सांसद हों या विधायक हों उनकी ऊर्जा में जीवन नहीं होगा, मृत्यु ही नाचेगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जो मीटर रीडिंग करने वाले लोग होते हैं, जैसे 110 में से 100 काट देंगे और 10 की रीडिंग करेंगे और अगर उन्हें दस प्रतिशत पूरे बिल का भुगतान मिल जाए नगदी में, तो इस तरह की गड़बड़िया कर देंगे। मेरा कहना है कि भ्रष्टाचार भी एक मुख्य कारण है। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन एक कमांऊ सपूत है विद्युत विभाग का। लाखों लोग उससे प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। यह घाटे में नहीं चल रहा है मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि निरंतर उसके उत्पादन और लाभ की जो दर थी विकास की, वह अवसान की ओर आती जा रही है। आपको इस ओर व्यक्तिगत रूचि लेनी है। मैं ध्वनि में बोल रहा हूं लोग व्यक्तिगत अपने हितचिंतन में उस संस्थान का उपयोग करना चाहते हैं जब बड़े-बड़े कल-कारखाने विद्युत के सिंचाई के पंडित जवाहर लाल नेहरू ने खडे किए थे तो उनको औधोगिक तीर्थ का नाम दिया था इन कल-कारखानों को।

4-00 P.M.

और आज जो हमारा टिहरी बांध है, मैं उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा मंत्री महोदय का कि कई सौं करोड़ रुपया उसका खर्च हो रहा हैं। रुपये का अवमूल्यन होता जा रहा हैं, निरन्तर अवमल्यन होता जा रहा हैं और जो इंजीनियर्स हैं, जो वास्तुकार हैं, जो टैक्नीशियस हैं वे इस तरह का काम

[डा रत्नाकर पाण्डेय]

कर रहे हैं कि जो पांच वर्ष में योजना पूरी होनी चाहिए वह शताब्दियों में पूरी हो । इसलिए निरंतर रुपया लगता जा रहा है, रिजल्ट हम कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं । क्या इसका सर्वे किया जाएगा कि टिहरी बांध कब तक बन जाएगा और उससे विद्युत उत्पादन कब तक शुरू हो जायेगा या इस तरह से लालफीताशाही में ही रुपया बहाकर पंचवर्षीय योजनाओं में ही उसका अंत हो जाएगा ? भूकम्प से वह बांध टूटेगा और पानी गांवों को बहा ले जाएगा और उससे जन-शक्ति का नुकसान होगा, इसको लेकर के पहाड़ के लोग विशेषत: बहुगुणा जी, जो वन आन्दोलन के जनक हैं, आंदोलन कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि टिहरी बांध की योजना कब तक पूरी कर दी जाएगी और उसको टाइम बाऊंड फ्रेम वर्क बनाने की कोई योजना है आपके पास ? है तो क्या है और नहीं है तो कोई योजना आप बनाएंगे और कार्यरूप में उसे परिणत करेंगे ताकि उत्पादन उसमें होने लगे ? रिहन्द के पानी का स्तर बराबर नीचे आता रहता है । क्या कोई स्थाई रूप से वाटर स्टोरेज टैंक जो एक लेवल रखे बरसात हो या ना हो, पानी स्टोर हो और उस पानी से विद्युत का उत्पादन होता रहे, ऐसी कोई टैक्नीकल समीक्षा रिहन्द या और भी जो देश में बड़े-बड़े बांध हैं जिनसे विधुत उत्पादन होता है, उनके लिए करना चाहते हैं ? करना चाहते हैं तो वह क्या है यह सदन आपसे जानना चाहता है ?

मैं उस नेता में विश्वास करता हूं जिसने उस देश को वचन दिया था, राजीव गांधी ने, कि 22,245 मेगावाट बिजली हम पैदा करेंगे ।

श्री राम अवधेश सिंह : 22 हजार गलत फिगर है, करेक्ट कर लीजिए ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : जब जानते नहीं हो चीजों को तो थोडा ट्राई टू स्टडी । और उतना उत्पादन अपने शासन काल के पहले उन्होंने कर दिया । आप क्या थे ? दो-दो सरकारें आई । एक को समर्थन देने का कलंक हमको भी है महज चार महीने का । नारा लगाया 40 साल बनाम 4 महीने । मरवा के फिकवा दिया गया राजीव गांधी को । इतनी निकम्मी और अशुभ सरकार आई चन्द्रशेखर की कि राजीव गांधी की धज्जियां उड़ाकर हमको दीं और तुलना की कि 40 साल कांग्रेस के और 4 महीने हमारे । 4 आदमी या 5 आदमी आए चन्द्रशेखर के दल का यह सारा देश देख रहा है, फ्रंडिज्म बहुत दिनों तक नहीं चलता है । 8वीं पंचवर्षीय योजना न वी.पी. सिंह फाइनलाइज कर पाए, न चन्द्रशेखर जी कर पाए । 8वी योजना का प्रारूप भी हमें ही निश्चित करना है । कल्पनाथ राय जी, मैं आपको तब मानूंगा जब विद्युत की जितनी योजनाएं हैं, उसका रुपया चाहे प्रणव मुखर्जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष हों, उनसे या भारद्वाज जो मिनिस्टर हों, उनसे नरसिंह राव जी प्राइम मिनिस्टर हों, उनसे आप पूरी योजना का रुपया लेंगे यह आश्वासन आप इस सदन को दीजिए नहीं तो आपकी भी वाणी में, चिंतन में, भावना में विभेद होगा । आपका भी दोहरा व्यक्तित्व माना जाएगा । यह सदन है, यहां प्लेटफार्म के भाषण नहीं चलते हैं । आप आश्वासन दीजिए कि आप 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो विद्युत का सारा रुपया प्लानिंग का है, वह लेंगे, लेंगे,लेंगे । यह आश्वासन दीजिए इस सदन को ।

विद्युत के उत्पादन के कई प्रकार हैं, उसके विस्तार में तो मैं नहीं जाना चाहता लेकिन राम अवधेश सिंह जैसे विवेक के दुश्मन भी यहां बैठे हुए हैं

इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि इस समय दुनिया में पांच प्रकार से बिजली का उत्पादन हो रहा है । हाइड्रो... (व्यवधान)

श्री राम अवधेश सिंह : आपको इतना विवेक हैं कि समझ सके कि किसी के पास विवेक है कि या नहीं डा० रत्नाकर पाण्डेय हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर, नान कंवशनल सोर्स आफ एनर्जी का सोलार थर्मल पावर और आंटोमिक पावर ।

इन पांच तरह से हम विद्युत का उत्पादन जो टेक्नोक्रेट्स हैं या दुनिया

में जो कुछ विद्युत का उत्पादन हो रहा है, हम कर रहे है । जो हमारे प्रोजेक्ट्स है उनका मूल्य निरंतर बढ़ रहा है, अधिक से अधिक उन पर निरंतर धनराशि खर्च होती जा रही हैं और भारत की जो अर्थव्यवस्था हैं उसके लिये थर्मल पावर बहुत ही उपयोगी हैं और उसको लेकर के जो हमारे उद्योग है, कुटीर उद्योगों की जो कल्पना गांधी जी ने की थी जिस पर हम आधारित है उस पर ऊर्जा अधिक लगती है । इस लिये जो कुछ भी हमारी अर्थव्यवस्था है उसे थर्मल पावर में अधिक से अधिक लगाना चाहिये । ऊर्जा उत्पादन के लिये उद्योग की आवश्यकता हैं और उद्योगों में जो ऊर्जा लग रही है, जो इडस्ट्रिज हैं उन्हे सरकार अपने यूनिट से पावर न दे । जैसे जैनेरेटर्स जगह-जगह लगे हैं, उस तरह से प्रत्येक कल-कारखानों को आदेश दिया जाये, चाहे वह प्राईवेट सैक्टर में हों, चाहे गवर्नमेंट में हों,चाहे नेशनल सैक्टर में हों वह स्वयं अपना ऊर्जा उत्पादन कर और उसकी व्यवस्था होनी चाहिये । तब जनता को, किसानों को, गरीबों को हम ऊर्जा दे सकते हैं । खेती के लिये बिजली की जरूरत है, कुटीर उद्योगों के लिये बिजली की जरूरत है । उपसभाध्यक्ष जी, आप भी एक गरीब प्रांत से आते हैं, हम भी एक गरीब प्रांत से आते हैं । उत्तर प्रदेश, बिहार और उडीसा यह तीनों गरीब प्रांत माने जाते हैं । यहां खम्भा तो गिरा दिया इंजीनियर साहब ने । कल्पनाथ राय जी से मैं जानना चाहता हूं कि पिछली बार जब राजीव गांधी जी के मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री थे तो कितनी प्रोजेक्ट्स का इन्होंने उद्घाटन किया देश भर में और उत्तर प्रदेश में व विशेषकर पूर्वांचल उसमें से कितनों पर इनका नाम खुदा और कितनों पर काम हुआ ? कोई भी सरकार हो, अगर कोई मंत्री काम करता हो और सरकार बदल जाती हैं तो उन कामों को रोकने का मकसद है जनता की आशाओं और विश्वास के साथ खुराफात करना मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जितने प्रोजेक्ट्स का इन्होंने उद्घाटन किया है यह शिलान्यास किया हैं या पत्थर लगाया हैं या जनता को आश्वासन दिया हैं वह कब तक पूरा करने जा रहे हैं और उसके लिए उनके पास पैसा है या नहीं ? यदि पैसा नहीं है तो बतायें ताकि फाइनेंस मिनिस्टर को पकड़कर हम लोग इनको पैसा दिलवायेंगे यह बताये कि कब तक इनको योजना टिरमिन है कि उनको पूरा करेंगे जितनी योजनाओं का पत्थर इन्होंने लगाया है और नाम खुदवाया है संगमरमर के पत्थरों पर ?

मैं जानना चाहता हूं कि एनर्जी लॉस जो होता हैं, इलैक्ट्रिसिटी की जो थैफ्ट होती है उनमें 30 प्रतिशत से ज्यादा बिजली चोरी होती हैं । मंत्री महोदय ने अभी दिल्ली में हजारों छापे मरवाये, सैकड़ों लोगों को जेल भिजवाया क्या उससे सुधार हो जायेगा ? इस पर गवर्नमेंट को कडा नियंत्रण करना पडेगा । जैसे बहुत से अरब कंट्रीज में अगर कोई चोरी करता हुआ पाया जाता है तो उसका हाथ काट लिया जाता है, उसको अंग-भंग कर दिया जाता हैं या उसकी आंख निकाल ली जाती है । परन्तु आपको यहां कोई कोर्ट मे जाकर स्टे आर्डर ले आये और फिर जो चाहे नौ हजार छापे मरवाये या 9 लाख मरवाये फिर उसी तरह से हो जाता है । तो फिर हमें अपना कानून कड़ा करना पड़ेगा ।

जो न्यूक्लिअर प्लांट हैं, गुजरात में समुद्र की लहरों के संचालन उसे विद्युत उत्पादन हो रहा है और मैंने देखा है कि कलपक्कम में बिजली का उत्पादन हो रहा हैं और ऊर्जा—सूरज की रोशनी से बिजली का उत्पादन हो रहा हैं । गैस जो हमें विद्युत की शक्ति प्रदान कर सकती हैं वह निरर्थक प्रवाहित हो रही हैं, प्रकृति को गंदा कर रही हैं और हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं । जिस देश में सिंचाई की कमी हो, बिजली की कमी हो और इतनी नदियां हों, और इतने समुद्र का जल हो उसके प्योरिफिकेशन का 44 साल में हमने प्लान नहीं किया तो उस और कुछ बड़े कंक्रीट काम करने के बाद हमारी चीजे ऐसी होंगी जिन पर हम गर्व कर सकते हैं ।]

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मेरे मित्र बार-बार इशारा कर रहे हैं कि मैं थोड़ा, बोलूं, इसलिए मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा । महोदय, कोयले और पानी से विद्युत का उत्पादन होता है । महोदय, आपको स्मरण होगा कि हम लोग आपके सभापतित्व में संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों के रूप में धनबाद गए थे । उसके एक दिन पहले ही भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर जी भी वहां गए थे । हम लोग वहां कोयला भवन में अतिथि थे और संयोग से मुझे उसी कमरे में टिकाया गया जिसमें पहले दिन चन्द्रशेखर जी रूके थे । महोदय, वहां के अधिकारियों ने रिकार्ड पर आप आए बिना मुझसे और समिति के सारे सदस्यों से कहा था कि जब भारत का प्रधानमंत्री कोयले के माफिया के यहां जाकर उन लोगों को चाय पीने के लिए भोजन करने के लिए विवश करेगा और फिर कहेगा कि कोयले की इंटरनेशनल सप्लाई इसको दे दो... **(व्यवधान)**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : यह गलत है ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : यह सत्य है और सत्य कहना कोई अपराध नहीं है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : यह एलीगेशन है । यह किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर एलीगेशन है जो इस सदन का सदस्य नहीं है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): माननीय सदस्य से मैं अनुरोध करूंगा कि कि व ऐसी बातें न कहें जिनसे उत्तेजना पैदा हो ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: क्या यह सत्य नहीं है ? हम लोग आपके सभापतित्व में ही वहां गए थे ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : मैं माननीय वक्ता महोदय से यह अनुरोध कर रहा हूं और माननीय मालवीय जी से कह रहा हूं कि इन्होंने किसी वैसे व्यक्ति के बारे में नहीं कहा है बल्कि भूतपूर्व प्रधानमन्त्री के बारे में कहा है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध यहां कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है जो सदन में उपस्थित होकर उसका खंडन न कर सके । मैं इसके बारे में आपकी व्यवस्था जानना चाहता हूं ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : उपसभाध्यक्ष महोदय, आप गवाह हैं, आपकी अध्यक्षता में हम लोग वहां गए थे ... **(व्यवधान)** यह सत्य है । उन्होंने कोयले के माफिया को संरक्षण दिया है और कोशिश की है कि उसे लाभ पहुंचाया जाए .. **(व्यवधान)**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : महोदय, मैं इस विषय पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं । मेरी आपत्ति यह है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध इस सदन में आरोप नहीं लगाया जा सकता है जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है और जो उसका खंडन यहां आकर नहीं कर सकता है इस बारे में नियम भी है और व्यवस्था भी है ... **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): माननीय सदस्य से मैंने अनुरोध किया है कि वे ऐसी कोई भी बात न कहें जिससे उत्तेजना पैदा हो ।

श्री राम अवधेश सिंह : उत्तेजना की बात आप क्यों पैदा कर रहे हैं ? यह व्यवस्था का सवाल है कि किसी बाहरी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाया जा सकता है या नहीं जो इस सदन में अपनी सफाई न दे सकता हो ..... **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : राम अवधेश जी, आप पहले मेरी बात सुनिए ... **(व्यवधान)** आप बैठिए तो मैं माननीय सदस्य श्री मालवीय जी से यह कहना चाहूंगा कि इन्होंने किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप नहीं लगाया बल्कि इन्होंने अपने भाषण में 3-4 भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों का नाम लिया । इसी क्रम में ये अपनी बात कह रहे थे ... **(व्यवधान)**

श्री राम अवधेश सिंह: अगर अभियोग लगाया तो उसे रिकार्ड से निकाला जाना चाहिए ...(**व्यवधान**) अगर अभियोग लगाने की ही परंपरा बन गई तो ...(व्यवधान)

डा० रत्नाकर पाण्डेय: माफिया गैंग को चन्द्रशेखर की सरकार ने संरक्षण दिया है, इसे मैं सिद्ध कर रहा हूं ... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): राम अवधेश जी, अगर कोई इस तरह की बात रिकार्ड में होगी तो हम देखेंगे लेकिन मैं रत्नाकर जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात विषय के अनुसार कहें क्योंकि 5 बजे मंत्री महोदय को उत्तर देना है और अभी कई वक्ताओं के नाम मेरे पास हैं।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: मैं 5 मिनट में समाप्त कर दूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): केवल दो मिनट।

डा० रत्नाकर पाण्डेय जैसी आपकी आज्ञा होगी।

श्री राम अवधेश सिंह: ये 35 मिनट पहले ही ले चुके हैं इसका भी तो ख्याल रखिए।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: राम अवधेश जी हर समय हमारे पीछे रहते हैं इसलिए हमको बोलने नहीं देते हैं

डा० रत्नाकर पाण्डेय: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मेरा मकसद किसी व्यक्ति विशेष के अपमानित करना नहीं है।...

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): आप मूल विषय पर आइए...

डा० रत्नाकर पाण्डेय: श्रीमन्, इस देश में कोयले से विद्युत का उत्पादन होता है। आप बिहार के रहने वाले हैं और वहां पर झरिया, कारकली, कटाहा नौन कोयले की बड़ी खानें हैं और कुल मिलाकर वहां पर छोटी-बड़ी 21 खाने हैं। हमारी हालत यह है कि हम 900 और 1200 रुपए प्रति टन के हिसाब से भारत में उत्पादन करते हैं लेकिन 4 हजार रुपए प्रति टन की दर से चीन से और 3 हजार रुपए प्रति टन की दर से आस्ट्रेलिया से मंगाते हैं। हमारी सरकार के लोग जाकर भारत की उत्पादित कोयले को ब्लैक करने की सिफारिश करते हैं। देश के सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान होकर शासन की बागडोर संभालते हैं, उनका नाम क्या है यह देश जानता है और आप भी जानते हैं। भारत के शासन में सबसे अधिक अल्पसंख्य दिन प्रधान मंत्री के रूप में ऐसी ही सरकारों का रहा है, ऐसे लोगों का रहा है जो चीजो को बढ़ाते हैं। आग लगी हुई है झरिया में, लेकिन उस आग को बुझाने के लिए उन्होंने क्या किया। हम वहां से आते हैं जहां सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन होता है, मिर्जापुर कमिश्नरी से, जहां थर्मल पावर के अनेक यूनिट हैं, सरकार के भी हैं और बिड़ला जी बैठे हैं, उनके भी हैं रेणुकूट में उनका प्राइवेट यूनिट है। ओबरा शक्तिनगर में सबसे बड़ा देश का उत्पादन होता है। लेकिन वहां कोयले की क्वालिटी सस्ती दी जाती है खराब दी जाती है। जब काम शुरू होता हैं तो वहां के इंजीनियर आंदोलन करके यूनियन बनाकर उत्पादन को प्रभावित करते हैं, उत्पादन रुक जाता है। वहां सत्ता के दलाल जाकर अपनी सप्लाई कराना चाहते हैं। मजदूरों की सप्लाई कराना चाहते हैं, अपने उत्पादन मैटीरियल की सप्लाई कराना चाहते हैं। इसके बावजूद भी सरकार के पास योग्य इंजीनियर हैं, टैक्नोक्रेट हैं। वहां जाने का मुझे मौका मिला है, मैं वहां की यूनियन का अध्यक्ष भी हूं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितनी तेजी के साथ वहां पर उत्पादन बढ़ा है वह उत्पादन और तेजी से बढे इस बात का प्रयास करना चाहिए क्योंकि ऊर्जा स्रोत के जो क्षेत्र हैं जब तक वे मजबूत नहीं होंगे तब तक हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। बिजली के अभाव को दूर करते

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

के लिए राज्य सरकार से केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए अनेक प्रपोजल भेज गए हैं. आप उन पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं, मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा।

इसके साथ ही कई राज्यों में छोटे छोटे पावर प्लांट हैं जो विशेषकर गैस पर आधारित प्लांट लगाने के उन्होंने सुझाव दिए हैं । मैं जानना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार उन पर क्या कार्यवाही कर रही है । सरकार को उन्हें शीघ्र मंजूर करना चाहिए और गस के माध्यम से ऊर्जा की सप्लाई का उचित प्रबंध राष्ट्रीय स्तर पर 8वां पंचवर्षीय योजना में करना चाहिए ताकि विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में क्रान्ति लाई जा सके ।

महोदय, पिछले दिनों जब कल्पनाथ राय जी वसंत साठे जी के साथ सहयोगी मंत्री के रूप में काम कर रहे थे तो उन्होंने प्राइवेट कम्पनियों को बिजली के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका देने की बात सोची और एक टाइम बाउंड प्रोग्राम तथा एकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हुए विद्युत वितरण और उत्पादन का काम देने की बात कही थी । बंबई में मैंने सुना है कि टाटा की बिजली सप्लाई कभी फेल नहीं होती है । लेकिन माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपके घर में बिजली फेल हो जाती है और कहा जाता है कि कनेक्शन जोड़ा जा रहा है और आठ-आठ, दस-दस घंट बिजली नहीं आती हैं । जिस देश में सांसदों को बिजली नहीं मिलती हो वहां पर हम गवर्नमेंट पर कैसे विश्वास करें तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए हमें विश्वास है कि कल्पनाथ राय जी इस ओर ध्यान देंगे ।

श्री राजीव गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब आप बिजली के क्षेत्र में क्रांति पैदा करेंगे । आपको श्रीमती सोनिया गांधी की कृपा मिली हैं । इसलिए आप सारे तथ्यों को सामने रखकर विश्वास दिलायें कि ऊर्जा के स्रोत को कभी कम नहीं होने देंगे । जिस तरह से सूरज की रोशनी प्रज्वलित रहती हैं, देश, समाज और वातावरण देती है उसी तरह से भारत के हर गांव, हर झोपड़ी, हर व्यक्ति को जो गरीबी की रेखा से नीचे रहता है, पददलित है, एक एकड़, दो एकड़ में खेती करता हैं, ऐसा मजदूर जो जमीनविहीन हैं, उस को आप रोशनी देंगे और रोशनी से जो शक्ति प्राप्ति होगी उससे राजीव गांधी की आत्मा की जय होगी, जय होगी, जय होगी ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : श्री नरेश सी० पुगलिया ।

श्री राम अवधेश सिंह: श्रीमन्, मेरा नाम पहले है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकरदयाल सिंह): इस सूची में आपका नाम छः लोगों के बाद है ।

श्री राम अवधेश सिंह : आप मेरे साथ न्याय कीजिये । मेरा नाम पहले था ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): मेरे पास जो सूची है, मैं उसी को पढ़ रहा हूं, अपनी ओर से कुछ नहीं बोल रहा हूं । मेरी ओर से अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा । आप श्री पुगलिया जी को बोलने दीजिये । मैंने उनका नाम पुकारा हैं ।

श्री राम अवधेश सिंह : ओरिजिनल सूची में मेरा नाम पहले था ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : आप उनको बोलने दीजिये । आपको भी मैं बुलाता हूं ।

मैं एक अनुरोध कर दूं कि मैं चाहता हूं कि 5 बजे मंत्री महोदय जवाब दे दें । इसलिए प्रत्येक सदस्य 5 मिनट बोलें । पुगलिया जी, आप तो बहुत ही समझदार और जानकार सदस्य हैं ।

श्री नरेश सी० पुगलिया (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, कालिम एटेंशन के माध्यम से देश के इस महत्वपूर्ण विषय को लाने का जिन सम्मानित सदस्यों ने प्रयास किया है और सभापति महोदय ने

[श्री राम अवधेश सिंह]

तमाम प्रोजेक्ट है, उनको आप शामिल करें। मेरा खासतौर पर यह सुझाव है, मैं चाहूंगा कि इस सुझाव के बारे में सरकार और खासतौर से कल्पनाथ राय जी, जो कि एक डायनमिक मिनिस्टर हैं, वे अवश्य विचार करेंगे। महोदय, पूर्व में आप भी बोल चुके हैं कि जहां कोयला उपलब्ध है उसी जगह वह प्रोजेक्ट होना चाहियें। लेकिन सरकार का निर्णय पोलिटिकल लेबल पर होता है। जहां पर कोयले का ट्रांसपोर्टेशन बहुत दूर से होता है वह प्रोजेक्ट एकानामिकल नहीं होता। महोदय, मेरे चन्द्रपुर जिले में महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, जो कि 2340 मैगावाट है का है। उसकी आखिरी यूनिट बनने जा रही है। लेकिन जो दूसरा एन.टी.पी.सी. का एक हजार मैगावाट का सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, उसके कोल लिंकेज के लिये, पहले जब वसंत साठे मिनिस्टर थे तो उन्होंने कोल सेक्रेटरी और इनर्जी सेक्रेटरी के साथ हमारी मीटिंग बुलाई थी और उन्होंने उनसे कोयला देने की बात कही थी लेकिन यह मामला पेंडिंग रहा। उसके बाद आरिफ मोहम्मद खान जब इस विभाग के मंत्री बन, तो उन्होंने भी मीटिंग बुलाई तब भी यह मामला पेंडिंग रहा और फिर जब कल्याण सिंह कालवी मंत्री बने तो उन्होंनेभी मीटिंग बुलाई और उसमेंनिर्णय हुआ कि ऐसी जगहों पर प्रोजेक्ट बनायें जायें जिसके 15 किलोमीटर रेडियस में कोयला उपलब्ध हो। डब्लू.सी.एल. जो कोल कम्पनी है, उसके द्वारा कोयला देने का प्राविजन है। वहां के किसान इसके लिये जमीन देने के लिये तैयार है। एन.टी.पी.सी. के लिये वहां के किसानों ने अपने को अरेस्ट भी करवाय है। ऐसी हालात को देखते हुए उसका कोल लिंकेज अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जानकारी न हमें है और न सरकार को है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस विषय में अवश्य अपने विचार रखेंगे और उसको पूरा करने में मदद करेंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जो स्टेट इलक्टासिटी बोर्ड है, उनके यहां बड़े गलत ढंग से काम चल रहा है सेन्टर की जो एफिसियेंसी है, हमारे स्टेट बोर्डों में भी वही एफिसियेंसी आनी चाहिये। लेकिन वह एफिसियेंसी वहां नहीं आ रही है। 74.4 परसेंट जो हमारे स्टट सेक्टर प्रोजेक्ट हैं उनकी तरफ मंत्री महोदय को पूरा ताकत के साथ ध्यान देना चाहिये और उनकी जो जो तकलीफें हैं उनको दुर करने की तरफ ध्यान देना चाहिये। स्टेट सेक्टर मे जो हमारे इलक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं राज्य सरकारों पर 6500 करोड़ की बकाया राशि है। मंत्री महोदय इस बारे में भी उचित निर्णय लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। खासकर आठवी पंचवर्षीय योजना में, मैं इसकी कंसलटेटिव कमेटी सदस्य रहने के नाते मुझे इसकी पूरी जानकारी है कि 48 हजार मैगावाट का रिकमेंडेशन आठवीं पंचवर्षीय योजना में और 62 हजार मैगावट का सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए किया गया था लेकिन प्लानिंग कमीशन ने सब कमेटी बना कर जो रिकमेंडेशन किया है वह 38369 मैगावाट का किया है और इन योजनाओं के लिए एक लाख अटठाइस हजार करोड़ रुपया जो लगने वाला है इसकी व्यवस्था केन्द्र सरकार जरूर करेगी और इस सेक्टर को जरूर प्रायटी देगी। इसके बीच में जो दिक्कतें आती हैं उस में पूरा ध्यान दे। कर हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना में पावर प्रोजेक्टस को कम्पलीट करने के लिए केन्द्र सरकार पूरी ताकत के साथ ध्यन देगी। (**समय की घंटी**) दो मिनट और लूंगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में गैस की कोई कमी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से बार बार कहा है कि हमारे यहां गैस वेस्ट हो रही है और इस गैस का इस्तेमाल गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट् में इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन इस संबंध में केन्द्र सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इसलिए केन्द्र सरकार को इस विषय में सोचना होगा। दूसरा जहां तक प्राइवेटाइज़ेशन का सवाल है, पिछली सरकार ने इस संबंध में एक निर्णय लिया था। मैं यह कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा

इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा करने का मौका दिया है, इस दोनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जिस महाराष्ट्र से यहां आता हूं वह देश में बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता राज्य है और जिस जिस से मैं आता हूं, चन्द्रपुर जिला, वह इस देश को बिजली भी देता है और कोयला भी देता है। इसलिए मुझे गर्व है कि मैं ऐसे जिले से आता हूं जो देश के कार्य में अपना हाथ बंटाता है। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि विद्युत शक्ति मानव के लिए ऐसी चीज हो गई है कि हर व्यक्ति इस पर निर्भर हो गया है और उसकी निर्भरता की सही ढंग से पूर्ति नहीं हो पा रही है। केन्द्रीय सरकार अगर सही ढंग से प्लानिंग नहीं करती है जिस का बुरा असर पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि अभी श्री वीरेन्द्र शाह जी ने कहा कि ट्रेजरी बेंचेज की जिम्मेदारी है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इसको ठीक करें। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना में इस देश की एकमात्र नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने बिजली के क्षेत्र में क्रांति पैदा की और सातवीं पंचवर्षीय योजना में श्री राजीव गांधी जी ने टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया और देश ने इस क्षेत्र में 96 परसेंट एचीवमेंट प्राप्त की। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सन् 1977 से 1980 तक एक समय आया जब बिजली के क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं हुआ, एक भी प्रोजेक्ट नहीं बनी और उसी तरह से पिछले दो सालों में जो पुरानी योजनायें थी जिनको केन्द्रीय सरकार ने मंजूरी दी थी उनमें से मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या एक भी योजना को सही ढंग से कार्यान्वित किया गया है? चाहे ट्रांसमिशन लाइन का सवाल हो, चाहे नई प्रोजेक्ट का सवाल हो, चाहे थर्मल पावर स्टेशन का सवाल हो। पिछले दिनों की निकम्मी सरकारों ने ऊर्जा के क्षेत्र में इस देश को बहुत पीछे लौटा दिया है। मेरी आपसे विनती है और मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इन सब हालातों को मद्दे नजर रखते हुए आप इसमें कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें। 1990 में यहां पर एक कान्फ्रेन्स हुयी। जिसमें देश के जो बिजली के क्षेत्र में एक्सपर्टस हैं, ऐसे 200 लोगों ने अपने विचार दिये थे। लेकिन उनके विचारों पर क्या अमल किया गया, उन पर क्या निर्णय लिया गया है, इसकी अभी तक कोई जानाकारी नहीं है। इसी प्रकार से इस डिपार्टमेंट में, यह सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा डिपार्टमेंट है, जिसने सारे देश में छठी और सातवीं योजनाओं में क्रांति ला दी है। लेकिन पिछले दो सालों से यह निकम्मा डिपार्टमेंट बना हुआ है। यहां अधिकारी अगर कोई फाइल सामने करते हैं, तो मंत्री महोदय या प्रधानमंत्री महोदय ने उस पर निर्णय नहीं लिया। इसके कारण आज हम तकलीफ में हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि 1950 में इस देश में 1712 मेगावाट बिजली तैयार होती थी। लेकिन 1990 में जो हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना खत्म हुई है, तो उस समय हमारे यहां बिजली का उत्पादन बड़े भारी पैमाने पर हुआ और उसमें हम आत्मनिर्भर हुए। उस वक्त केवल 7 परसेंट बिजली की कमी थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो पुराने प्रोजेक्ट हैं, खासकर सातवीं पंजवर्षीय योजना में जो टारगेट, पाण्डेय जी ने भी कहा कि 22245 जमैगावाट का जो टारगेट था उसको हमने 96 परसेंट अचीव किया है। इसी प्रकार से इस योजना में जो हमारा टारगेट हैं, खासकर आठवीं पंचवर्षीय योजना का, मंत्री महोदय को ही इसका पता नहीं है। हम पिछले दो सालों से इस योजना की तरफ पूरी ताकत के साथ देख रहे हैं कि इसमें कौन से नये प्रोजेक्ट आने वाले हैं और कौन से नहीं आने वाले हैं। यहां पर दो सरकारें बदली लेकिन आठवीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा अभी तक तैयार नहीं है। प्लानिंग कमीशन पिछले दो सालों से यह सोच रहा है कि इनको हम पकड़ें या छोड़ दें। इस तरह से इन दो सालों में इस क्षेत्र में बरबादी हुई है। मैं मंत्री महोदय सेज विनती करूंगा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस देश के जो

महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है लेकिन न तो कन-सलटेटिव कमेटी में कभी इस की चर्चा हुई और न कोई सेमिनार बुला कर चर्चा की गई। मेरी जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार के पास 5300 मैगावाट केपेसिटी के लिए एप्लीकेशंस एन०आर०आई०, और इंडस्ट्रीयलिस्टस की तरफ़ से सरकार के पास आई है। मंत्री महोदय अपने उत्तर में अवश्य स्पष्ट करें कि प्राइवेटाइज़ेशन के लिए यह जो 5300 मैगावाट के प्रोपोजल जो आपके पास आए हैं इनमें कितने देश के उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं और कितने देश के बाहर से आए हैं और सरकार इन पर क्या निर्णय लेने जा रही है? जहां तक ऊर्जा बचाने का सवाल है केन्द्र सरकार इस संबंध में क्या करने जा रही है। हमें यह जानकारी दी गई है कि हमारे यहां 21–22 परसेंट ट्रांसमिशन लासेज़ हो रहे हैं इसके बारे में आप जरूर गौर करें कि इन लासेज़ को कैसे कम से कम किया जा सकता है। **(समय की घंटी)** उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक दो और सवाल करना चाहता हूं। हमारे यहां पर पावर थैफट बहुत ज्यादा हो रही है। हमारी सरकार को चाहिए कि पावर की चोरी सख्ती से बंद करे। पावर चोरी करने वालों के साथ आपको कड़ाई से निपटना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस में आप जरूर मदद करेंगे। इसी प्रकार से मैंने चन्द्रपुर प्रोजेक्ट के बारे में कहा था एन०टी०पी०सी० के कोयला लेने के विषय में आप अपने उत्तर में जरूर कहेंगे। आपने मुझे अपने विचार इस चर्चा के माध्यम से रखने का मौका दिया इस के माध्यम से सरकार कोई न कोई रास्ता निकालेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अनन्त राम जायसवाल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जब कभी ऊर्जा संकट पर चर्चा होती है तो तीन चार कारण गत बीस वर्षों से गिनाए जाते हैं इनकी तोता-रटत होती रहती है। जैसे मिसाल के लिए जितनी हमारी इंस्टाल्ड क्षमता है उसका हम पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दूसरा यह बताया जाता है कि ट्रांसमिशन लाइनों में यहां बिजली प्रेषण और वितरण में 22 प्रतिशत या इससे भी अधिक हानि होती है। तीसरी चीज़ यह है कि बिजली बोर्डों का घाटा बहुत होता है और चौथी चीज़ यह है कि हमारे पास संसाधनों की हमेशा कमी रही है और आज भी है। तो यह कारण बीस सालों से बराबर गिनाए जा रहे हैं चाहे यह मंत्री गिनाएं या चाहे इनके पहले वाले मंत्री गिनाते रहे हों। सदन जानना चाहता है कि क्या इन कारणों को दूर करने के लिए कोई उपाय किये गये हैं अगर किये गए हैं तो इनका विवरण क्या है और यदि नहीं किये गये तो क्यों? क्योंकि यह कारण तो बराबर गिनाए जाते रहे हैं, बीस सालों से गिनाए जाते रहे हैं, आजतक इन पर ध्यान नहीं गया यह प्वाइंटेड सवाल उठता है कि आखिर इनको दूर करने के क्या उपाय किये गये हैं। दूसरी चीज़, मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ अन्य देशों की अपेक्षा हमारे यहां ट्रांसमिशन और वितरण में बहुत नुकसान होता है। तो इसके कारण क्या हैं? मैं समझता हूं कि इसका कारण इसके बजाय कि ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं वह मजबूत नहीं हैं या ट्रांसमिशन की लाइनों पर लोड ज्यादा है, यह मुख्य कारण नहीं हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, इसका मुख्य कारण यह है किइस में खूब चोरी होती है।

उस चोरी को रोकने में इसलिए पूरा डिपार्टमेंट असमर्थ रहता है कि उसके बड़े अफसर से लेकर छोटे कर्मचारी तक उसमें शामिल रहते हैं। मैं आपको बता दूं पहले खाली बड़े बड़े लोग ही चोरी किया करते थे, बड़े बड़े कारखानेदार किया करते थे लेकिन माननीय मंत्री जी आज एक भी ऐसा घर नहीं होगा चाहे दिल्ली में या पूरे देश में जहां बिजली की चोरी न होती हो। आप इसका पता लगाइये और इस में सख्ती से कुछ कोशिश कीजिए, जैसे दूसरी जगहों पर छीजन होती है हानि होती है बिजली की उसके मुकाबले में इसको लाने की कोशिश करें। क्या इसके लिए कोई उपाय आप करेंगे। इस पर अपने भाषण में प्रकाश डालिएगा।

तीसरी चीज, मैं कहना चाहता हूं कि जब बिजली की इतनी कमी है और

(श्री अनंत राम जायसवाल)

यह बेसिक नेसेसिटी है, एक आवश्यक इनपुट है जिसकी खेती में भी जरूरत है, कारखाने में भी जरूरत है, घरेलू कामों के लिए भी उसकी जरूरत है तब फिर इसको बढ़ाने के लिए पूरे प्रयास होने चाहिए ।

आपूर्ति की वास्तविकता आज दिल्ली में ही आप देख लीजिए, दिल्ली का सामला ले लीजिए । इस महीने बिजली के कारण ऐसी दुश्वारियों से लोगों को गुजरना पड़ा कि लोगों को भगवान याद आ गये । यहां तक गुस्सा बढ़ गया कि दिल्ली का ही एक गांव है बाला जहां के लोग सड़क जाम करने पर मजबूर हो गये । अगर बिजली चली जाती है तो उसके साथ पानी भी गायब हो जाता है । चाहे उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी, पश्चिमी या पूर्वी दिल्ली ले लीजिए, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर बिजली और बिजली के साथ पानी की कमी न रही हो । इसके कारण लोगों में ऐसा रोष आया कि वे सड़क जाम करने पर उतर आये । इससे कानून और व्यवस्था का भी प्रश्न जुड़ गया है । फिर शिकायतों को कहां पहुंचाया जाय ? शिकायतों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है । यही बहुत बड़ी शिकायत है "डेसू" के खिलाफ कि इन शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही नहीं की जाती । उपसभाध्यक्ष जी । एक आपने ही सुझाव दिया था कि सब-स्टेशनों पर बोर्ड लगा दिया जाए जिससे लोगों को दूर से ही समझ में आ जाए कि बिजली क्यों गयी है और कब तक मिल जाएगी । हमारा ख्याल है कि मंत्री जी इसकी तरफ ध्यान देंगे ।

चौथी चीज, मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने वक्तव्य को देखिए, चाहे जितना संतोष आपका डिपार्टमेंट कर ले, आप कर लें, लेकिन आपके वक्तव्य के पेज तीन के पैरा 8 में आपने खुद माना है कि 193 बिलियन यूनिट्स की बजाये । 180 बिलियन यूनिट्स के पैदा होने की संभावना है, आशा है और वह इसलिए है कि कोयले की सप्लाई पूरी नहीं होगी । कोयले की सप्लाई पर यहां बहुत जोर दिया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कमी को दूर करने की क्या कोई कोशिश कोल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर की जा रही है, कोयले की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया गया है या नहीं, या कब तक उठाया जाएगा ? इसमें यह भी कहीं जिक्र नहीं है कि जो यह कमी होगी उसको और किन स्रोतों से पूरा करेंगे, हाइडल से पूरा करेंगे, या गैस जो बह रही है उससे पूरा करेंगे । अब वक्त आ गया है कि जितने बिजली उत्पादन के स्रोत हैं चाहे कोयले से हो, पानी से हो, गैस से हो या समुद्र की लहरों से ही क्यों न हो, इन सबका दोहन होना चाहिए । इन सब के बारे में आपका आश्वासन मिले तो यह सदन आपको धन्यवाद देगा ।

बहुत बहुत धन्यवाद ।

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (Assam): Mr. Vice-Chairman, honourable Members have already drawn a dark and dismal picture of the...

श्री राम अवधेश सिंह : मान्यवर, क्या मेरा समय नहीं आयेगा ।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : लेडीज पर दया करो ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): राम अवधेश जी, ऐसा है कि आप तो माननीय सदस्य हैं और काफी विज्ञ भी हैं... (**व्यवधान**) आप देखिए, हमारे पास जो सूची बनकर आती है वह सचिवालय वाले बनाकर देते हैं । यहां जो भी पीठासीन व्यक्ति हों उनको यह कर्तव्य होता है कि उसको देखते हुए उसका पालन करे । फिर भी कोई सदस्य जल्दबाजी में रहता है या कोई कारण उनका होता है तो निश्चय ही उनको देते हैं ।

श्री राम अवधेश सिंह : मुझको बाहर जाना है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): इसलिए आप इनके बाद तैयार रहें। लेकिन साथ ही साथ पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

SHRIMATI BIJOY CHAKRAVARTY: Sir, honourable Members have already drawn a dark and dismal picture of the problem, of our crisis, in the country. Many reports have been tabled in the House on power, non-conventional power, general power, hydroelectric power, .orrja projects, and so on. All the reports have drawn a bright, utopian picture, devoid of any truth. The Government lacks drive and energy and motivation to act and do some fresh thinking at the need of the hour and in this crisis. Due to this crisis the formers are not getting proper and adequate water supply and the industries had to be shut down. The students, professors and doctors, all are suffering a lot in this country. So far as the domestic consumption is concerned, the less said the better. In Delhi itself those who are living outside the purview of New Delhi have to live without electricity for three consecutive days. Even today there is no power in my own house in the South Avenue area. Sir, in the North Eastern reglon power cut is a regular and a general feature and many industries had to be shut down because of this crisis. The new entrepreneurs, the new young boys who were encouraged by the AGP Government to start industries had to shut down their industry. You know Sir, the condition they may create. Secondly, power cuts not only in Assam but in the entire North Eastern region has become a tradition and puts the people in a great predicament. The people now resort to using generators. This shows that people have lost faith in the power of the Government to supply power. By using generators on a very large scale they have to use valuable diesel oil to run these generators and this is a great loss to the country. So I think the Government should have a fresh and realistic thinking in this regard. There are many reports on power, on energy, on non-conventional source of energy, I know of so many projects in Assam. People used to give serious thought on these projects and reports. But, when they started getting an unsympathetic attitude from the Central Government they stopped thinking. If the hon. Minister wants, I shall submit a report in this regard. Sir, this country is full of resources. There are so many rivers. In the North Eastern region the hydroelectric department can very easily harness the water resources for harnessing power in this country. Essentially in Assam I know of many projects and reports which are lying in cold storage.

The Brahmaputra, the Subansiri and Darang projects, if they have been utilised, I know electricity could be supplied to this country at a very cheap rate from North Eastern region to UP. But, I don't know why these projects had been shelved. These projects would also stop erosion in Assam. I want to know from the hon Minister whether the Minister is really thinking of doing something in this regard. Will the Ministry come out with a time-bound programme for proper utilisation of the project so that the supply of electricity crisis could be minimised? Secondly, we know there is gas available near all the oil-fields. The gas is burnt for years together. There are so many projects in Assam and in other parts of the country where oil is in abundance. So again I request the hon. Minister to sanction these gas-based power projects. The cost may be high, but ultimately it is a productive cost. In the long run the cost will be minimised on these projects. I hope the hon. Minister gives thought to this and give the green signal. I will conclude by saying one thing. Most of the electricity boards are running at a great loss So the Government has to spend a large amount of money for monitoring all these sick public sector boards. In this regard many hon. Members have already spoken and voiced their

[Shrimati Bijoy Chakraverty]
opinion that this power department should be privatised. I hope the hon. Minister will give thought to this. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : श्री राम अवधेश सिंह, 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : मान्यवर, आपने समय सीमा बांध दी है इसलिए कुछ अपने को सीमित करना ही है क्योंकि सवेरे सभापति महोदय के सामने बात-चीत हुई थी ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) वह बात छोड़ दीजिए, मेन बात बोलते जाइए ।

श्री राम अवधेश सिंह : मैंने यह कहा कि मैंने अपना स्पेशल मेंशन इस विषय पर इस आधार पर वापस ले लिया कि आज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, पावर की सप्लाई के बारे में बहस हो रही है उसी में अपनी बात पूरे विस्तार से कह लीजिए इसलिए आपको यह मेंशन नहीं दिया जाए और आपने 5 मिनट की सीमा बांध दी । फिर भी मैं अपनी बात संक्षेप में कहने की कोशिश करूंगा ।

मान्यवर, इस विषय में किसी की दो राय नहीं हैं कि बिजली की आपूर्ति कम होने पर देश के पूरे उत्पादन का चक्का जाम हो जाता है या जितना कम होता है उसी हिसाब से उत्पादन भी कम होता है और औद्योगीकरण का विकास भी नहीं हो पाता है । मझे खेद इस बात का है कि भारत सरकार उस स्थान की उपेक्षा करती रही है जहां बिजली आपूर्ति करने की पूरी क्षमता है । मतलब बिजली आपूर्ति का पूरा साधन जहां है उस स्थान की उपेक्षा होती रही है । बिहार में पूरे देश का 45 फ़ीसदी से ले कर 50 फ़ीसदी कोयला निकलता है और वहां से कोयला पंजाब में जाता है आन्ध्र में भी जाता है, हरियाणा में जाता है, तमाम सूबों में जाता है और वहां ताप बिजलीघर बनते हैं और उनकी आवश्यकता के अनुसार बिजली पैदा होती है । हमारे यहां मान्यवर, आज की तारीख में 1350 मेगावाट बिजली पैदा करने की इन्स्टाल्ड कैपेसिटी है वैसे तो आंकड़ा है कि मीमो आफ़ अंडरस्टेंडिंग के मुताबिक 4438 मेगावाट की स्थापना की बात कही जा रही है लेकिन असल उत्पादन बिहार में 450–500 मेगावाट से ज्यादा नहीं हो पाता है । ... (व्यवधान) मैंने अधिकतम सीमा बताई है । उससे अधिक नहीं हो पाता है । इस पर मैं चाहूंगा कि यह भारत सरकार ध्यान दे और बिहार सरकार और बिहार इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड तो इतना निकम्मा है और इस काम के लायक नहीं है कि यह काम कर सके जितना जल्दी हो सके बिजली की आपूर्ति बिहार में करने की कोई नई योजना बनाई जाए, कोई नई एजेंसी तैयार की जाए, जो कि इस काम को कर सके । मान्यवर, भारत सरकार की बेईमानी और उत्तर प्रदेश सरकार की बेईमानी हम लोगों के साथ होती रही है । रिहन्द डैम के बारे में आपको शायद मालूम होगा और हिन्दुस्तान की जितनी नदियां हैं जो अन्तर्प्रांतीय हैं उससे अगर नदी बहती है, कोई बांध लगता है तो बिजली और पानी में बंटवारा उन दोनों-तीनों राज्यों में होता है और होता रहा है और हर जगह हुआ है । डी०वी०सी० में भी हम लोगों ने बंटवारा किया है । बंगाल को दिया है, उत्तरा को दिया है, बिहार को बंटा है । नर्मदा नदी में भी बांटा है । यह कावेरी नदी में भी बंटा है, लेकिन एक नदी है रिहंद डैम जो बना है, जो बिहार उत्तर प्रदेश से हो करके आती है, जो डैम बना उसमें यह समझौता हुआ था कि जो पनबिजली निकलेगी वह उत्तर प्रदेश जाएगी और पानी बिहार को मिलेगा । 18 हजार क्यूसेक फीट पानी बिहार को और 300 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को मिलेगी । तो बिजली तो सारी की सारी वहां चली गई इस बेईमानी के तहत और हमको जो पानी मिलना था । 18 हजार क्यूसेक फीट वह भी नहीं मिला और 1988 से लगातार हमारे इलाके के धान सूख रहे हैं ।

तो 88 के अक्टूबर महीने में मैंने धरना दिया।

श्री कल्पनाथ राय : क्यों नहीं मिला ?

श्री राम अवधेश सिंह : बेईमानी उत्तर प्रदेश सरकार करती रही है। यह क्यों करते हैं, पूर्व मुख्य मंत्री बताएं? यह सब जगह बंटवारा हुआ, लेकिन बिहार के साथ बेईमानी हुई। बिहार के लोग कमजोर हैं, वे इस लड़ाई को नहीं लड़ पा रहे हैं।... (*व्यवधान*) ... पानी तो हमको मिलना चाहिए न ?

श्री कल्पनाथ राय : उन्होंने दे दिया पानी।

श्री राम अवधेश सिंह : नहीं बिजली दी है। पानी भी तो तुम सिंगरौली में लेकर चले जा रहे हो। हमारे खेत हर साल सूख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस बारे में हमको दर्द है।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : यू० पी० वाले शोषण कर रहे हैं।.. (*व्यवधान*)...

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : राम अवधेश जी, आप अपनी बात कहें।

श्री राम अवधेश सिंह : मान्यवर, मैं यह कह रहा हूं कि एक तो पानी की कमी हो गयी रिहन्द डैम से। एक और डैम बाणसागर डैम, मध्यप्रदेश में बन रहा है। जिस दिन वह तैयार हो जाएगा तो जो थोड़ा-बहुत पानी सोन नहरों को मिलता है, वह भी नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कि सोन नहरें भारत की सबसे पुरानी नहरों में से हैं और इस व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है। जिस दिन बाणसागर डैम बन जाएगा, उस दिन हमको एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। भोजपुर, रोहतास, बक्सर, भगुआ, औरंगाबाद, गया, पटना, कलग—इन 9 जिलों की भूमि मरुभूमि में बदल जाएगी। मान्यवर, आप जानते हैं कि ये इलाके बिहार के भोजन देनेवाले इलाके हैं, लेकिन ये मरुस्थल में बदलने वाले हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए एक कदवन जलाशय परियोजना की भारत सरकार ने मंजूरी दी थी। इस कदवन परियोजना में 450 मेगावाट बिजली भी बनती और साथ-ही-साथ हमको 27 हजार क्यूसिक फीट पानी की व्यवस्था भी होती। लेकिन मान्यवर, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसकी नींव पड़ गयी, वहां अफसरों के मकान बनने लगे, तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री सत्यनारायण सिन्हा ने उद्घाटन कर दिया अक्टूबर 89 में, लेकिन आज आठवीं पंचवर्षीय योजना में, मुझे विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली है कि एक पैसा भी कदवन जलाशय परियोजना पर नहीं दिया गया। अब फिर से कहा जा रहा है कि सेंट्रल वाटर कमीशन उसको रोके हुए है। उस पर सो गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके लिए क्या उपाय है? आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूं, आप भी कुछ कहिए कि अगर कदवन जलाशय परियोजना चालू नहीं हुई तो क्या होगा? मान्यवर, कोयल कारो प्रोजेक्ट दस साल से मंजूर है। हमारे लायक दोस्त श्री कल्पनाथ राय जी जो ऊर्जा मंत्री हैं, पिछली दफा जब मंत्री थे तो इन्होंने आश्वासन भी अपनी ओर से दिया कि हम अपनी ओर से करेंगे और इन्होंने कराया भी।

* उसका नाम है पी०आई०बी० यानी पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड। पता नहीं वहां कैसे लोग बैठे हैं?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, ये अन-पार्लियामेंटरी लैंग्वेज बोल रहे हैं। पी०आई०बी० एक इंस्टीट्यूट है सरकार के नीचे। वहां अफसर बैठते हैं। * । इन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : राम अवधेश जी, आप इस शब्द को वापिस ले लीजिए।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : अगर वह प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो आप उनको * कैसे कहेंगे? कल को वह कहें कि

*Expunged as ordered by the Chair.

आप कटघरे में * की तरह बिहेव करते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : ठीक है, आप बैठ जाइए, वह संशोधन कर लेंगे ?

श्री राम अवधेश सिंह : अपनी जाति को आप पहचान गए ...(**व्यवधान**)... यह कहा जाता है कि आदमी एक विचारशील * है। वहां बैठे विचारशील बिना विचार किए किसी योजना को खटाई में डाल देते हैं, इसलिए मैंने कहा कि अविवेकशील * वहां बैठे हैं । आदमी तो विवेकशील * है।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : मान्यवर, यह बोलनेवाले * को अब बंद किया जाए, बहुत समय हो गया है ।

श्री राम अवधेश सिंह : विवेकशील * आदमी है, इस बारे में शक नहीं है । इसकी परिभाषा है । मैं यह कह रहा था...

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : सुनिए आप । जहां तक रिकार्ड की बात है, किसी भी व्यक्ति के लिए * शब्द नहीं जाएगा।

श्री राम अवधेश सिंह : व्यक्ति के लिए मैंने नहीं कहा । संगठन, एक ऐसा संगठन है जो...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : आप किसके बारे में कह रहे हैं । आप उल्टी-पुल्टी बात करते हैं यहां पर । ...(**व्यवधान**)... आप हिंदी के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उपाध्यक्ष महोदय । इस सदन की मर्यादा का सवाल है कि आप एक संगठन को, जिसकी मदद से सरकार चलती है, उनके सदस्यो को आप * कहेंगे ?

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : आप देखिए, मैंने कह दिया ।

श्री राम अवधेश सिंह : मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि हमारे राज्य में पनबिजली की इतनी कमी है कि रात में शहर अंधेरे में डूबा रहता है । बिजली आपूर्ति के बारे में एक नियम है कि 60 और 40 का अनुपात होना चाहिए यानी अगर ताप बिजली 60 यूनिट है तो पन-बिजली 40 यूनिट होनी चाहिए, इसलिए कि पनबिजली में एक सुविधा है कि पांच मिनट के अंदर ही जनरेशन शुरू हो जाती है और ताप बिजली में अगर चलाएंगे तो रात में तो यह ठीक होगी, दिन में जरूरत नहीं हुई तो उत्पादित बिजली बेकार जाएगी । इसलिए किसी भी मुल्क में 60:40 का अनुपात होना चाहिए । बिहार में तो 90 और 10 का भी अनुपात नहीं है । यही कारण है कि हमारी सारी इंडस्ट्रीज तबाह हैं और रात में हमको बिजली नहीं मिल पाती है । तो कोयलकारो प्रोजेक्ट उस हिसाब से बहुत जरूरी है । उसको दबाया गया है । इसलिए मैंने कहा कि अविवेकशील लोग बैठे हुए हैं और हमारी आवश्यकता को समझ नहीं रहे हैं और पूरे राज्य के विकास के ऊपर सो गए हैं।...

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : बहुत हो गया, राम अवधेश जी। धन्यवाद। श्री माधवन।

श्री राम अवधेश सिंह : नहीं-नहीं। मैंने तीखी भाषा का प्रयोग इसलिए किया, कोई अपमानजनक नहीं । तीखी भाषा का प्रयोग इसलिए किया कि उनके दिमाग के भीतर घुस सके कि हम कितना अविवेकशील काम कर रहे हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : आप शुरू कीजिए, माधवनजी ।

श्री राम अवधेश सिंह : अच्छा, एक लाईन और बोल देता हूं । मान्यवर, यह भी कहा गया हैं कि कोयले की आपूर्ति बाहर से की जा रही हैं, कोयला आयात किया जा रहा हैं । इसमें मुझको बहुत जरूरी बात कहना हैं कि जो चार हजार टन, साढ़े तीन हजार टन कोयला बाहर से आयात किया जाता हैं, उसमें भारी

*Expunged as ordered by the Chair.

घपलेबाजी होती है। यह कोयला आयात किया जाता है स्टील उत्पादन के लिए क्योंकि हमारे कोयल में कहा जाता है कि राख की मात्रा ज्यादा है। राख की मात्रा ज्यादा होने से उत्पादन में कठिनाई होती हैं, लकिन मुझको जो सूचना मिली है, उसकी जांच कराई जाए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि मेरी सूचना के अनुसार 100 करोड़ रुपए का जो कोयला आयातित हुआ उसमें से 39 करोड़ रुपए का कोयला चोर-बाजारी में बेच दिया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो जहाज के बंदरगाहों पर कोयला उतरा, कितना उतरा?...

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): माधवन जी, प्लीज आप शुरू कीजिए। नहीं तो मैं नेक्सट स्पीकर को बुला रहा हूं। नेक्सट स्पीकर श्री के० जी० महेश्वरप्पा।

श्री राम अवधेश सिंह: नहीं नहीं कदवन जलाशय परियोजना चालू होगी या नही? मैं यह जानना चाहता हूं और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस साल यह कोयलकारो प्रोजेक्ट शुरू होगा या नहीं? इसका आश्वासन मंत्री जी से नहीं मिलेगा तो मैं सदन की कार्यवाही नहीं चलने दूंगा। मैं इसलिए कह रहा हू। (व्यवधान)... मैं नहीं बैठूंगा। मैं चाहता हूं कि इस सदन में मंत्री जी मौजूद हैं, यह बात हमको बताए।

5.00 P.M.

मेरे दर्द को आप समझने की कोशिश करिए क्योंकि जो मंजूर हो गया और मंजूर होने के बाद वह काम आगे क्यों नहीं हो रहा? मैं साफ-साफ जानना चाहता हूं। मैं आश्वासन चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): अब रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है। देखिए राम अवधेश सिंह जी, अब आप जो बोल रहे हैं, रिकार्ड में नहीं जा रहा है। उनके दिल में चला गया हैं, दिमाग में चला गया है।

श्री राम अवधेश सिंह: यह हमको बता दें कि यह कोयलकारो प्रोजेक्ट चालू होगा या नहीं और कदवन जलाशय परियोजना चालू होगी या नहीं? मैं यह जानना चाहता हूं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बात होगी। अगर आप भाषण में बोल दें।...

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): भाषण में यह बोलेंगे, जब जवाब देने लगेंगे तो बोलेंगे।

श्री राम अवधेश सिंह आप जिम्मेवारी ले लीजिए कि यह बोलेंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): मैं निश्चित रूप से इन सभी बातों के बारे में यह बोलेंगे।

SHRI S. MADHAVAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, I welcome the assurance of the Minister that he is going to take all steps to increase power generation. Of course, he is to face difficulties from the finance department for approving many projects pending in various States. The Government must take certain policy decisions expeditiously. For example, hydel project. We have not taken up many projects wherever there are river disputes between two States. The Government of India must come forward to take a bold decision to take the project under Central sector. We have developed a regional grid system. The Government of India is to come forward to develop national grid system, so that the power-hungry States will be benefited from other States. Atomic energy power plant comes completely under the purview of the Central Government. Why there is so much delay. It must be looked into. So far as thermal plants are concerned every State wants to develop thermal plant. But the problem is coal supply. Coal supply and the railway transport facilities have to be coordinated by the Government of India. States have to face many sufferings and always come to the Centre for help.

Now, about the question of policy decision about private sector. Pri-

vate sector is prepared to participate in the power generation. The State Governments are formulating the policies. But why is the Government of India not able to take speedy decisions on these policy matters? Hon. Minister must take into consideration the fact that special attention is to be paid to the States where there is acute shortage of power. For example, Tamil Nadu, the Southern State is always power-hungry. The only hydel project which is pending because of the Cauvery dispute is Hogenakal. If the State Governments are not able to solve this problem then the Central Government must take up this Hogenakal power project. It will produce about 1000 magawatts. Another example in Tamil Nadu is about atomic project recently sanctioned for the Southernmost district of Tamil Nadu State. The State Government is giving full support to this project and in spite of that the Government of India has not made any progress in putting up this atomic plant in Tamil Nadu. Then, they have developed many coal based thermal plants in Tamil Nadu. But we are always facing difficulties in the supply of coal. We have to depend on other States for supply of coal. I remember coming to the Minister in the Central Government department to rectify these difficulties and to arrange for transport facilities and coal availability from the coal mining areas. Another factor in Tamil Nadu is where there is coal shortage in Tamil Nadu, why is the Government of India reluctant to give sanction to exploit available lignite in Neyveli area and Javamcondan areas in Tamil Nadu State? It is a long pending issue. The Government of India in the Central sector is running Neyveli corporation but they are not able to go ahead with much progress in many stages in Neyveli mining and power projects. Now the State Government along with the private sector have given proposals to the Prime Minister to start these joint sector projects to exploit Neyveli lignite and Jayam condan lignite available in Tamil Nadu State. Hon. Minister has to help Tamil Nadu State where there is acute power shortage.

About gas supply, former Minister—now the Leader of Opposition — had promised southern pipe gas supply to Tamil Nadu. The present Minister must take up this project and help Tamil Nadu by giving southern pipeline to Tamil Nadu from the Western States.

Government of India has taken steps to develop Thanjavur district area. Now the gas is coming out. The Government of India must try to invest more money in these areas for finding more gas and using it for gas-based plants and also gas-based industry. The State Government has given a number of proposals to the Centre and the Centre must help the State of Tamil Nadu because there is acute shortage of power. The Minister must take up all the proposals pending with the Government of India submitted by our new Government under the leadership of Miss Jayalalitha. She is coming to meet the Prime Minister and is bringing proposals of the projects for development of Tamil Nadu and the Hon. Minister must give full attention to our proposals.

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): ऐसा है कि इस चर्चा को आज हम यहीं स्थगित कर रहे हैं। अब इस सूची में चार वक्ता रह गये हैं—श्री के० जी० महेश्वरप्पा, डा० शिवाजी, श्री सरेश पचौरी और श्री पवार। मंत्री महोदय को जवाब भी देना है।

श्री जगदीश प्रशाद माथर (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। पहले पद्धति यह थी कि कॉलिंग एटेंशन पर एक पार्टी से एक व्यक्ति बोलता था। तो यह पद्धति इस वक्त क्या अपनायी गयी है? एक पार्टी से एक बोलेगा या डिबेट के समय के अनुसार समय दिया गया है?

डा० रमाकर पाण्डेय : जितना अधिक पार्टीसिपेशन होगा उतना अच्छा है ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Tomorrow, we have the Business Advisory Committee, and we can discuss the point that has been raised here.

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : माथुर साहब, कल बिजनिस एडवाइजरी कमेटी में इस पर हम लोग बातें करके क्लिअर करेंगे । आप इसको यहां इसलिये स्थगित कर रहे हैं कि मंत्री महोदय को अभी लोक सभा जाना है । वहां पर वोट आफ कांफिडेंस के ऊपर वोट है, यह लोक सभा के सदस्य हैं । इसलिये अब हम स्पेशल मेंशन लेने जा रहे हैं ।

वे चार व्यक्ति जिनके नाम अभी मैंने कहे हैं, पहले वह बोलेंगे और उसके बाद मंत्री महोदय जवाब देंगे । स्पेशल मेंशन--

श्री सुरेश कलमाडी	अनुपस्थित
श्री कृष्ण लाल शर्मा	अनुपस्थित
श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर	अनुपस्थित
श्रीमती कमला सिन्हा	अनुपस्थित

SPECIAL MENTIONS

Police firing on Harijan Students in Tripura

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, त्रिपुरा, के विषय में मुझसे पहले भी अनगिनत आवाजें इस सदन में उठायी जाती रही हैं । लेकिन हर आवाज नक्कारखाने में तूती की आवाज बनकर रह गयी है । जुल्म, अत्याचार और अनाचार वहां इन्तहा को पार करता जा रहा है । उपसभाध्यक्ष महोदय, जुल्म करने वाले यह हाथ, अन्याय करने वाले यह हाथ, अत्याचार करने वाले यह हाथ आज वहां के शासक वर्ग की ताजपोशी कर रहे हैं और तख्तपोशी कर रहे हैं । इसलिए महोदय, मैं आज इस सदन में आपके दरवाजे पर इस आशा के साथ दस्तक देना चाहती हूं कि :

"दस्तकों का अब किवाड़ों पर असर होगा जरूर
हर हथेली खून से तर और ज्यादा बेकरार ।"

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही दुखी मन के साथ यह कहना चाहती हूं कि आज त्रिपुरा के जो हालात हैं वे हालात ऐसे हैं कि उन हालात को देखकर लगता है कि त्रिपुरा शायद हमारे देश का हिस्सा नहीं है । या त्रिपुरा हमारे देश का हिस्सा है तो निश्चित रूप में भारत का संविधान वहां काम करता होगा । यदि त्रिपुरा हमारे देश का हिस्सा है तो निश्चित रूप में भारत का संविधान वहां लागू होता होगा लेकिन महोदय, हालत यह है कि वहां जनतंत्र काम नहीं कर रहा है, कोई कानून वहां काम नहीं कर रहा है । महोदय, मैं आपका ध्यान 8 जुलाई की उस घटना की ओर दिलाना चाहती हूं जब शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे छात्रों को पुलिस की निर्मम गोलियों का सामना करना पड़ा । इन छात्रों ने कौन सा जुर्म किया था, कौन सा अन्याय किया था ? अगर पाठ्य-पुस्तकों की कालाबाजारी को लेकर त्रिपुरा का छात्र समाज शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करता है तो क्या यह जुर्म है ? क्या यह अन्याय है ?

महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहती हूं कि इन शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर वहां की पुलिस ने बड़े ही निर्मम ढंग से गोलियां चलाई और 7 राउंड गोलियां चलाई और उनके चलते वहां का आठवीं कक्षा का एक छात्र कानूदे बुरी तरह जख्मी हुआ और अगले दिन अस्पताल में उसकी मौत हो गई तथा अनगिनत छात्र आज भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और मौत से जूझ रहे हैं ।

[उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अनाजी मासोदकर) पीठासीन हुए]

महोदय, हालत इतनी गंभीर है कि जब इस वाकये की ओर मुख्यमंत्री का